

भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ
2. परिभाषाएँ
3. 1872 के अधिनियम संख्यांक 9 के उपबन्धों का लागू होना

अध्याय 2

भागीदारी की प्रकृति

4. "भागीदारी", "भागीदार," फर्म" और "फर्म नाम" की परिभाषा
5. भागीदारी प्रास्थिति के सृष्ट नहीं होती
6. भागीदारी के अस्तित्व के अवधारण का ढंग
7. इच्छाधीन भागीदारी
8. विशिष्ट भागीदारी

अध्याय 3

भागीदारों के एक दूसरे के प्रति सम्बन्ध

9. भागीदारों के साधारण कर्तव्य
10. कपट से कारित हानि के लिए क्षतिपूर्ति करने का कर्तव्य
11. भागीदारों के अधिकारों और कर्तव्यों का अवधारण भागीदारों के बीच की संविदा द्वारा होगा व्यापार अवरोधी करार
12. कारबार का संचालन
13. पारस्परिक अधिकार और दायित्व
14. फर्म की सम्पत्ति
15. फर्म की सम्पत्ति का उपयोजन
16. भागीदारों द्वारा उपर्जित वैयक्तिक लाभ
17. भागीदारों के अधिकार और कर्तव्य फर्म में तब्दीली होने के पश्चात् फर्म की अवधि के अवसान के पश्चात्, और जहाँ की अतिरिक्त उपक्रम किए गए हों

अध्याय 4

पर-व्यक्तियों से भागीदारों के सम्बन्ध

18. भागीदार फर्म का अभिकर्ता है
19. भागीदार का फर्म के अभिकर्ता के नाते विवक्षित प्राधिकार
20. भागीदार के विवक्षित प्राधिकार का विस्तार और निर्बन्धन
21. भागीदार का आपात में प्राधिकार
22. फर्म के आबद्ध करने के लिए कार्य करने का ढंग
23. भागीदार द्वारा स्वीकृतियों का प्रभाव
24. कार्यकारी भागीदार को दी गई सूचना का प्रभाव
25. फर्म के कार्यों के लिए भागीदार का दायित्व
26. भागीदार के सदोष कार्यों के लिए फर्म का दायित्व
27. भागीदारों द्वारा दुरुपयोजन के लिए फर्म का दायित्व
28. व्यपदेशन
29. भागीदार के हित के अन्तरिती के अधिकार

30. अप्राप्तवयों को भागीदारी के फायदों में सम्मिलित करना

अध्याय 5

अन्दर आने वाले और बाहर जाने वाले भागीदार

31. भागीदार का प्रविष्ट किया जाना
32. भागीदार का निवृत्त होना
33. भागीदार का निष्कासन
34. भागीदार का दिवाला
35. मृत भागीदार की सम्पदा का दायित्व
36. बाहर जाने वाले भागीदार को प्रतियोगिता कारबार चलाने का अधिकार व्यापार अवरोधी करार
37. कुछ दशाओं में बाहर जाने वाले भागीदार का पश्चातवर्ती लाभों में अंश पाने का अधिकार
38. चलत प्रत्याभूति का फर्म में तबदीली होने से प्रतिसंहरण

अध्याय 6

फर्म का विघटन

39. फर्म का विघटन
40. करार द्वारा विघटन
41. वैवश्यक विघटन
42. किन्हीं आकस्मिकताओं के गठित होने पर विघटन
43. इच्छाधीन भागीदारी का सूचना द्वारा विघटन
44. न्यायालय द्वारा विघटन
45. विघटन के पश्चात् किए गए भागीदारों के कार्यों के लिए दायित्व
46. विघटन के पश्चात् कारबार का परिसमापन कराने का भागीदारों का अधिकार
47. परिसमापन के प्रयोजनों के लिए भागीदारों का सत प्राधिकार
48. भागीदारों के बीच लेखा परिनिर्धारण का ढंग
49. फर्म के ऋणों और पृथक् ऋणों का संदाय
50. विघटन के पश्चात् उपार्जित वैयक्तिक लाभ
51. समयपूर्व विघटन में प्रीमियम की वापसी
52. अधिकार, जहाँ कि भागीदारों की संविदा कपट या दुर्व्यपदेशन के कारण विखंडित कर दी गई है।
53. फर्म नाम या फर्म की सम्पत्ति को उपयोग में लाने से अवरूद्ध करने का अधिकार
54. व्यापार अवरोधी करार
55. विघटन के पश्चात् गुडविल का विक्रय गुडविल के क्रेता और विक्रेता के अधिकार

अध्याय 7

फर्मों का रजिस्ट्रीकरण

56. इस अध्याय से लागू होने से छूट देने की शक्ति
57. रजिस्ट्रारों की नियुक्ति
58. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

59. रजिस्ट्रीकरण
60. फर्म नाम में और कारबार के मुख्य स्थान में हुए परिवर्तनों का अभिलेख
61. शाखाओं के बन्द करने और खोलने का टिप्पणित किया जाना
62. भागीदारों के नामों और पतों में तब्दीलियों का टिप्पणित किया जाना
63. फर्म में तब्दीलियों और उसके विघटन का अभिलेखन अप्राप्तवय के प्रत्याहरण का अभिलेखन
64. भूलों का परिशोधन
65. न्यायालय के आदेशों से रजिस्टर का संशोधन
66. रजिस्टर और फाइल की गई दस्तावेजों का निरीक्षण
67. प्रतियों का दिया जाना
68. साक्ष्य के नियम
69. रजिस्ट्री न कराने का प्रभाव
70. मिथ्या विशिष्टियां देने के लिए शक्ति
71. नियम बनाने की शक्ति

अध्याय 8

अनुपूरक

72. लोक सूचना देने का ढंग
73. (निरसित)
74. व्यावृत्तियां
अनुसूची 1—अधिकतम फीस
अनुसूची 2—(निरसित)

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932

1932 का अधिनियम संख्यांक 9

8 अप्रैल 1932

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ – (1) यह अधिनियम भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 कहा जा सकेगा।
 - (2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवास संपूर्ण भारत पर है।
 - (3) यह सन् 1932 के अक्टूबर के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा, सिवाय धारा 69, के जो सन् 1933 के अक्टूबर के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगी।
2. परिभाषाएँ—इस अधिनियम में जब तक कि कोई बात विषय या सन्दर्भ में विरुद्ध न हो—
 - (क) “फर्म का कार्य” से फर्म के सब भागीदारों या किसी भागीदार या किसी अभिकर्ता का कोई भी कार्य या लोप अभिप्रेत है जिससे फर्म के द्वारा या विरुद्ध प्रवर्तनीय कोई अधिकार उद्भूत होता हो,
 - (ख) “कारबार” के अन्तर्गत हर व्यापार, उपजीविका और वृत्ति आती है।
 - (ग) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है,
 - (घ) “पर-व्यक्ति” पद से जब यह किसी फर्म या उसके किसी भागीदार के संबंध में प्रयुक्त किया गया है ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो फर्म में भागीदार नहीं है, तथा
 - (ङ) उन मदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त किए गए हैं, किन्तु इसमें परिभाषित नहीं हैं और भारतीय संविदा अधिनियम, 1872, (1872 का 9) में परिभाषित हैं, वे ही अर्थ होंगे जो उन्हें अधिनियम में समनुदिष्ट हैं।
3. 1872 के अधिनियम संख्यांक 9 के उपबन्धों का लागू होना – भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनिरसित उपबन्ध वहाँ तक के सिवाय, जहाँ तक कि इस अधिनियम के अभिव्यक्त उपबन्धों से असंगत हैं, फर्मों को लागू होते रहेंगे।

अध्याय 2

भागीदारी की प्रकृति

4. "भागीदारी", "भागीदार", "फर्म", "फर्म नाम" की परिभाषा – "भागीदारी" उन व्यक्तियों के बीच का सम्बन्ध है, जिन्होंने किसी ऐसे कारोबार के लाभों में अंश पाने का करार कर लिया है जो उन सबके द्वारा या उनमें से ऐसे किन्हीं या किसी के द्वारा जो उन सब की ओर से कार्य कर रहा है, चलाया जाता है।

वे व्यक्ति जिन्होंने एक दूसरे से भागीदारी कर ली है, व्यक्ति: "भागीदारी" और सामूहिक रूप से "फर्म" कहलाते हैं और जिस नाम से उनका कारबार चलाया जाता है, वह "फर्म नाम" कहलाता है।

5. भागीदारी प्रास्थिति से सृष्ट नहीं होती – भागीदारी सम्बन्ध संविदा से उद्भूत होता है, प्रास्थिति से नहीं,

और विशेषकर हिन्दु अभिभक्त कुटुंब के सदस्य, जो उस हैसियत में कौटुंबिक कारबार चलाते हैं, या बर्मी बौद्ध पति और पत्नी, जो उस हैसियत में कारबार चलाते हैं, ऐसे कारबार में भागीदार नहीं हैं।

6. भागीदारी के अस्तित्व के अवधारण का ढंग—यह अवधारण करने में कि व्यक्तियों का कोई समूह फर्म है या नहीं अथवा कोई व्यक्ति किसी फर्म में भागीदारी है या नहीं, पक्षकारों के बीच के उस वास्तविक संबंध का ध्यान रखा जाएगा जो सब सुसंगत तथ्यों को एक साथ लेने से दर्शित होता हो।

स्पष्टीकरण 1— संपत्ति से उद्भूत लाभों या कुल प्रत्यागमों का उस संपत्ति में संयुक्त या सामान्य हित रखने वाले व्यक्तियों द्वारा अंश पाना स्वयंमेव ऐसे व्यक्तियों को भागीदार नहीं बना देता,

स्पष्टीकरण 2— किसी व्यक्ति द्वारा किसी कारबार के लाभों में से किसी अंश कि या किसी कारबार में लाभ उपार्जित होने पर समाश्रित, या उपार्जित हुए लाभों के अनुसार घटने बढ़ने वाले किसी संदाय की प्राप्ति स्वयंमेव उस कारबार को चलाने वालों का भागीदार नहीं बना देती :-

और विशिष्टतया —:

(क) ऐसे व्यक्तियों को धन उधार देने वाले द्वारा जो किसी कारबार में लगे हुए या लगने ही वाले हों,

(ख) किसी सेवक या अभिकर्ता द्वारा पारिश्रमिक के रूप में,

- (ग) किसी मृत भागीदार की विधवा या अपत्य द्वारा वार्षिकी के रूप में, अथवा
- (घ) कारबार के किसी पूर्वतन स्वामी या भागिक स्वामी द्वारा उस कारबार के गुडविल या अंश के विक्रय के प्रतिफलस्वरूप, ऐसे अंश या संदाय को प्राप्ति पाने वाले को उस कारबार को चलाने वाले व्यक्तियों का स्वयंमेव भागीदार नहीं बना देती।
7. इच्छाधीन भागीदारी – जहाँ कि भागीदारों के बीच की संविदा द्वारा उनकी भागीदारी की अस्तित्वावधि के लिए या उनकी भागीदारी के पर्यवसान के लिए कोई उपबन्ध नहीं किया गया है, वहाँ वह भागीदारी "इच्छाधीन भागीदारी" है।
8. विशिष्ट भागीदारी—कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का विशिष्ट प्रोद्यमों अथवा उपक्रमों में भागीदार बन सकेगा।

अध्याय 3

भागीदारों के एक दूसरे के प्रति सम्बन्ध –

9. भागीदारों के साधारण कर्तव्य—भागीदार सर्वाधिक सामान्य फायदे के लिए फर्म के कारबार को चलाने, एक दूसरे के प्रति विश्वासपरायण और वफादार रहने, तथा हर भागीदार या उसके विधिक प्रतिनिदि को सच्चा लेखा और फर्म पर प्रभाव डालने वाली सब बातों की पूरी जानकारी देने के लिए आबद्ध है।
10. कपट से कारित हानि के लिए क्षतिपूर्ति करने का कर्तव्य—हर भागीदार उस हर हानि के लिए फर्म की क्षतिपूर्ति करेगा जो फर्म के कारबार के संचालन में उसके कपट से फर्म को कारित हुई हो।
11. भागीदारों की अधिकारों और कर्तव्यों का अवधारण भागीदारों के बीच की संविदा द्वारा होगा—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्याधीन यह है कि फर्म के भागीदारों के पारम्परिक अधिकारों और कर्तव्यों का अवधारण भागीदारों के बीच की संविदा द्वारा किया जा सकेगा और ऐसी संविदा अभिव्यक्त हो सकेगी या व्यवहार चर्या से विवक्षित हो सकेगी। ऐसी संविदा में फेरफार सब भागीदारों की सम्मति से किया जा सकेगा और ऐसी सम्मति अभिव्यक्त हो सकेगी या व्यवहार चर्या से विवक्षित हो सकेगी।
- (2) व्यापार अवरोधी करार—भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का 9) की धारा 27 में किसी बात के होते हुए भी ऐसी संविदाएं

उपबन्ध कर सकेगी कि कोई भागीदार, जब तक वह भागीदार रहे, फर्म के कारबार के सिवाय कोई और कारबार नहीं करेगा।

12. कारबार का संचालन – भागीदारों की बीच की संविदा के अध्यक्षीन यह है कि—
- (क) हर भागीदार को कारबार के संचालन में भाग लेने का अधिकार है,
 - (ख) हर भागीदार आबद्ध है कि वह कारबार के संचालन में अपने कर्तव्यों का तत्परतापूर्वक पालन करें,
 - (ग) कारबार से संसक्त मामूली बातों के बारे में उद्भूत किसी भी मतभेद का विनिश्चित भागीदारों के बहुमत से किया जा सकेगा और हर भागीदार को इससे पहले कि मामले का विनिश्चय हो अपनी राय अभिव्यक्ति करने का अधिकार होगा, किन्तु कारबार की प्रकृति में कोई भी तब्दीली सब भागीदारों की सम्मति के बिना नहीं की जा सकेगी, तथा
 - (घ) हर भागीदार को फर्म की बहियों में किसी भी बही तक पहुंच का और उसका निरीक्षण और उसकी नकल करने का अधिकार है।
13. पारम्परिक अधिकार और दायित्व— भागीदारों की बीच की संविदा के अध्यक्षीन यह है कि—
- (क) भागीदार कारबार के संचालन में भाग लेने के लिए पारिश्रमिक पाने का हकदार नहीं है,
 - (ख) भागीदार उपार्जित लाभ में समानतः अंश पाने के हकदार हैं और फर्म को हुई हानियों में समानतः अभिदाय करेंगे,
 - (ग) जहाँ कि कोई भागीदार अपनी लगाई हुई पूंजी पर ब्याज पाने का हकदार है, वहाँ ऐसे ब्याज केवल लाभों में से ही संदाय होगा,
 - (घ) कोई भी भागीदार जो ऐसी पूंजी के अतिरिक्त, जिसे लगाने का करार उसने उस कारबार के प्रयोजनों के लिए किया है, कोई संदाय या अभिदाय करता है, उस पर छह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज पाने का हकदार है,
 - (ङ) भागीदार द्वारा निम्नलिखित में किए गए संदायों या उपगत दायित्वों की बावत फर्म उसकी क्षतिपूर्ति करेगी—
 - (1) उस कारबार का मामूली और उचित संचालन, तथा

(2) हानि से फर्म की संरक्षा करने की प्रयोजन से आपात् में ऐसा कार्य करना जैसा मामूली प्रज्ञा वाले व्यक्ति द्वारा अपने मामले में वैसी ही परिस्थितियों में किया जाता, तथा

(च) भागीदार उस हानि के लिए फर्म की क्षतिपूर्ति करेगा जो फर्म के कारबार के संचालन में जानबूझकर उसके द्वारा की गई उपेक्षा से फर्म को कारित हुई हो।

14. फर्म की सम्पत्ति— भागीदारों के बीच की संविदा के अध्यक्षीन यह है कि फर्म की सम्पत्ति के अन्तर्गत फर्म के स्टॉक में मूलतः लाई गई या फर्म द्वारा या फर्म के लिए या फर्म के कारबार के प्रयोजनार्थ और अनुक्रम में क्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित सब सम्पत्ति और संपत्ति में के अधिकार और हित आते हैं और इसके अन्तर्गत कारबार का गुडविल भी आता है।

जब तक कि तत्प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो, फर्म के धन से अर्जित संपत्ति और संपत्ति में के अधिकार और हित फर्म के लिए ही अर्जित समझे जाते हैं।

15. फर्म की सम्पत्ति का उपयोजन—भागीदारी की बीच की संविदा के अध्यक्षीन यह है कि फर्म की संपत्ति भागीदारों द्वारा अनन्यतः कारबार के प्रयोजनों के लिए धारित और उपयोजित की जाएगी।

16. भागीदारों द्वारा उपार्जित वैयक्तिक लाभ— भागीदारों के बीच की संविदा के अध्यक्षीन यह है कि —

(क) यह कोई भागीदार फर्म के किसी संव्यवहार से या फर्म की संपत्ति या कारबारी संबंध या फर्म नाम के उपयोग से अपने लिए कोई लाभ व्युत्पन्न करता है तो वह उस लाभ का लेखा—जोखा फर्म को देगा और उस लाभ का संदाय फर्म को करेगा।

(ख) यदि कोई भागीदार फर्म के बराबर की ही प्रकृति का और प्रतियोगी और कारबार चलाता है, तो वह उस कारबार में अपने को हुए सब लाभों का लेखा—जोखा फर्म को देगा और उन सब लाभों का फर्म को संदाय करेगा।

17. भागीदारों के अधिकार और कर्तव्य — भागीदारों के बीच की संविदा के अध्यक्षीन यह है कि—

(क) फर्म में तब्दीली होने के पश्चात — जहां कि फर्म के गठन में कोई तब्दीली घटित होती है, वहां पुनर्गठित फर्म में भागीदारों के पारम्परिक अधिकार

और कर्तव्य यावत्शक्त वैसे ही बने रहते हैं जैसे वे उस तब्दाली के अव्यवहित पूर्व थे।

- (ख) फर्म की अवधि के अवसान के पश्चात और जहां कि नियत अवधि के लिए गठित फर्म उस अवधि के अवसान के पश्चात कारबार चलाती रहती है, वहां भागीदारों के पारम्परिक अधिकार और कर्तव्य जहां तक कि वे इच्छाधीन भागीदारी की प्रसंगतियों से संगत हो वैसे ही बने रहते हैं जैसे वे अवसान के पूर्व थे तथा
- (ग) जहां के अतिरिक्त उपक्रम किए गए हों जहां कि एक या एक से अधिक प्रोद्यम या उपक्रम चलाने के लिए गठित फर्म अन्य प्रोद्यम या उपक्रम चलाती है, वहां उन अन्य प्रोद्यमों या उपक्रमों के बारे में भागीदारों के वे ही पारस्परिक अधिकार और कर्तव्य होते हैं जो मूल प्रोद्यमों या उपक्रमों के बारे में हों

अध्याय 4

पर—व्यक्तियों से भागीदारों के सम्बन्ध

18. भागीदार फर्म का अभिकर्ता है — इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यायीन यह है कि भागीदार फर्म के कारबार के प्रयोजनों के लिए फर्म का अभिकर्ता होता है।
19. भागीदार का फर्म के अभिकर्ता के नाते विवक्षित प्राधिकार (1) धारा, 22 के उपबन्धों के अध्याधीन यह है कि भागीदार का ऐसा कार्य, जो उस किस्म के कारबार को, जैसा फर्म चलाती है, प्रायिक रीति में चलाने के लिए किया गया है, फर्म को आबद्ध करता है।
- फर्म को आबद्ध करने का भागीदार का प्राधिकार जो इस धारा द्वारा प्रदत्त है, उसका विवक्षित प्राधिकार कहलाता है।
- (2) व्यापार को किसी तत्प्रतिकूल प्रथा या रूढ़ि के अभाव में, भागीदार का विवक्षित प्राधिकार उसे सशक्त नहीं करता है कि वह —
- (क) फर्म के कारवार से सम्बन्धित विवाद को मध्यस्थम् के लिए निवेदित करे,
- (ख) फर्म की ओर से बैंक में स्वयं अपने नाम में खाता खोले
- (ग) फर्म द्वारा किए गए किसी दावे या दावे कि किसी भाग का समझौता करे या उसे त्याग दे,

- (घ) फर्म की ओर से फाइल किए गए किसी वाद या कार्यवाई का प्रत्याहरण करे
- (ङ.) फर्म के विरुद्ध किसी वाद या कार्यवाही में कोई दायित्व स्वीकृत करे,
- (च) फर्म की ओर से स्थावर सम्पत्ति अर्जित करे
- (छ) फर्म की स्थावर सम्पत्ति अन्तरित करे, अथवा
- (ज) फर्म की ओर से भागीदारी में सम्मिलित हो।

20. भागीदार के विवक्षित प्राधिकार का विस्तारण और निर्बन्धन फर्म के भागीदार भागीदारों के बीच की संविदा द्वारा किसी भी भागीदार के विवक्षित प्राधिकार का विस्तारण या निर्बन्धन कर सकेंगे।

ऐसे किसी निर्बन्धन के होते हुए भी, भागीदार द्वारा फर्म की ओर से किया गया कोई भी कार्य, जो उसे विवक्षित प्राधिकार में आता है, फर्म को आबद्ध करता है, जहां तक कि वह व्यक्ति जिसके साथ वह भागीदार व्यौहार कर रहा है उस निर्बन्धन को जानता न हो या यह ज्ञान या विश्वास रखता है कि वह भागीदार भागीदार नहीं है।

21. भागीदार का आपात में प्राधिकार – भागीदार का आपात में यह प्राधिकार है कि वह हानि से फर्म की संरक्षा करने के प्रयोजन से ऐसे सब कार्य करे जैसे मामूली प्रज्ञा वाले व्यक्ति द्वारा अपने निजी मामले में बैसी ही परिस्थितियों में कार्य करते हुए किए जाते और ऐसे कार्य फर्म को आबद्ध करते हैं।

22. फर्म को आबद्ध करने के लिए कार्य करने का ढंग – इसलिए कि वह फर्म को आबद्ध करे फर्म की ओर से भागीदार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य या निष्पादित लिखत फर्म नाम में या किसी ऐसे अन्य से, जिससे फर्म को आबद्ध करने का आशय अभिव्यक्ति या विवक्षित होता हो, किया जाएगा या निष्पादित की जाएगी।

23. भागीदार द्वारा स्वीकृतियों का प्रभाव – भागीदार द्वारा फर्म के मामलों में सम्पृक्त स्वीकृति या व्यपदेश फर्म के विरुद्ध साक्ष्य है, यदि वह कारबार के मामूली अनुक्रम में किया गया हो।

24. कार्यकारी भागीदार को दी गई सूचना का प्रभाव – जो भागीदार फर्म के बराबर में अभ्यासतः कार्य करता रहता है, उसे फर्म के मामलों से सम्बन्धित किसी बात की

सूचना फर्म की दी गई सूचना का प्रभाव रखती है सिवाय उस दशा के जब कि इस उस भागीदार द्वारा या उसकी सम्पत्ति से फर्म से कपट किया गया हो।

25. फर्म के कार्यों के लिए भागीदार का दायित्व – हर भागीदार, फर्म के ऐसे सब कार्यों के लिए जो उसके भागीदार रहते हुए किए जाते हैं, अन्य सब भागीदारों के साथ संयुक्त: दायी है और पृथक् भी।
26. भागीदार के सदोष कार्यों के लिए फर्म का दायित्व – जहां कि किसी फर्म के कारबार के मामूली अनुक्रम में या अपने भागीदारों के प्राधिकार से कार्य करते हुए भागीदार के सदोष कार्य या लोप से किसी पर-व्यक्ति को हानि या क्षति कारित होती है या कोई शास्ति उपगत होती है, या फर्म उसके लिए उसी विस्तार तक दायी है जहां तक कि वह भागीदार है।
27. भागीदारों द्वारा दुरुपयोजन के लिए फर्म का दायित्व जहां कि—
 - (क) भागीदार अपने दृष्यमान प्राधिकार के अन्दर कार्य करते हुए किसी पर व्यक्ति से धन या सम्पत्ति प्राप्त करता है और उसका दुरुपयोजन करता है, अथवा
 - (ख) फर्म अपने कारोबार के अनुक्रम में किसी पर व्यक्ति से धन या सम्पत्ति प्राप्त करती है और भागीदारों में से कोई उस धन या सम्पत्ति का जब वह फर्म की अभिरक्षा में है दुरुपयोजन करता है।

वहां फर्म हानि का प्रतिपूर्ति करने के लिए दायी है।

28. व्यपदेशन – (1) जो कोई मौखिक या लिखित शब्दों द्वारा या आचरण द्वारा यह व्यपदेशन करता है या जानकर यह व्यपदेशन किया जाने देता है कि वह किसी फर्म में भागीदार है, वह उस फर्म के भागीदार के नाते ऐसे किसी भी व्यक्ति के प्रतिदायी है जिसने ऐसे किसी व्यपदेशन के भरोसे उस फर्म को प्रत्यय दिया है, चाहे वह व्यक्ति जिसने अपने भागीदार होने का व्यपदेशन किया है या भागीदार होने का व्यपदेशन किया गया है यह ज्ञान रखता हो या नहीं कि वह व्यपदेशन ऐसे प्रत्यय देने वाले व्यक्ति तक पहुंचा है।
 - (2) जहां कि किसी भागीदार की मृत्यु के पश्चात ही कारबार पुराने फर्म नाम से चालू रखा जाता है, वहां उस नाम का या मृतक भागीदार के नाम का उस कारबार के भागस्वरूप उपयोग किए जाते रहना स्वयमेव उस मृतक्

भागीदार के विधिक प्रतिनिधि या उसकी सम्पदा को फर्म के ऐसे कार्य के लिए, जो उसकी मृत्यु के पश्चात किया गया हो, दायी नहीं बना देगा।

29. भागीदार के हित के अन्तरिती के अधिकार (1) किसी भागीदार द्वारा फर्म में अपने हित का आत्यन्तिक रूप से या बन्धक द्वारा या ऐसे हित पर अपने द्वारा किसी भाग के सृजन द्वारा किया गया अन्तरण अन्तरिती को फर्म के चालू रहने तक यह हक नहीं देता कि वह फर्म के कारबार के संचालन में हस्ताक्षेप करे या लेखा आपेक्षित करे या फर्म की वाहियों का निरीक्षण करे, किन्तु वह अन्तरिती को केवल यह हक देता है कि वह अन्तरक भागीदार के लाभों का अंश प्राप्त करने तथा भागीदारों द्वारा माना गया लाभों का लेखा अन्तरिती प्रतिगृहित करेगा।

(2) यदि फर्म विघटित कर दी जाती है या अन्तरक-भागीदार, भागीदार नहीं रह जाता तो अन्तरिती शेष भागीदारों के मुकाबले फर्म की आस्तियों में वह अंश जिसका अन्तरक-भागीदार हकदार है, पाने का और इस प्रयोजन से कि उस अंश को अभिनिश्चित किया जाए फर्म के विघटित होने की तारीख से लेखा लेने का हकदार है।

30. अप्राप्तवयों को भागीदारी के फायदों में सम्मिलित करना – (1) वह व्यक्ति, जो उस विधि के अनुसार, जिसके वह अध्यक्षीन है, अप्राप्तवय है, फर्म में भागीदार नहीं हो सकेगा, किन्तु सब तत्समय भागीदारों की संपत्ति से उसे भागीदारी के फायदों में सम्मिलित किया जा सकेगा।

(2) ऐसे अप्राप्तवय का अधिकार है कि वह फर्म की संपत्ति और लाभों का ऐसा अंश पाए जैसे का करार किया गया हो और फर्म के लेखाओं में किसी भी लेखे तक उसकी पहुंच हो सकेगी और वह उनमें से किसी का भी निरीक्षण और नकल कर सकेगा।

(3) ऐसे अप्राप्तवय का अंश फर्म के कार्यों के लिए दायी है किन्तु वह अप्राप्तवय ऐसे किसी कार्य के लिए वैयक्तिक रूप से दायी नहीं है।

(4) ऐसा अप्राप्तवय फर्म की संपत्ति या लाभों में के अपने अंश के लेखे के लिए या संदाय के लिए भागीदारों पर वाद नहीं ला सकेगा सिवाय जब कि वह फर्म से अपना सम्बन्ध विच्छेद करता हो और ऐसी दशा में उसके अंश की रकम का अवधारण ऐसे मूल्यांकन द्वारा किया जाएगा जो यावत्संभव धारा 48 में अन्तर्विष्ट नियमों के अनुसार किया गया हो:

परन्तु ऐसे वाद में फर्म के विघटन का निर्वाचन, सब भागीदार एक साथ कार्य करते हुए, या फर्म का विघटन करने का हकदार कोई भी भागीदार, दूसरे भागीदारों को सूचना देकर कर सकेगा और तदुपरि न्यायालय उस वाद में ऐसे कार्यवाही करेगा मानो वह वाद विघटन के लिए और भागीदारों के बीच लेखा परिनिर्धारण के लिए हो और अप्राप्तवय के अंश की रकम को भागीदारों के अंशों के साथ-साथ अवधारित किया जाएगा।

(5) उसके प्राप्तवय हो जाने की तारीख और उसे यह ज्ञान कि वह भागीदारी के फायदों में सम्मिलित कर लिया गया है अभिप्राप्त हो जाने की तारीख में से जो भी पश्चात की तारीख हो उसके छह मास के अन्दर किसी भी समय ऐसा व्यक्ति यह लोक सूचना दे सकेगा कि उसने फर्म में भागीदार होने का निर्वाचन या न होने का निर्वाचन कर लिया है और ऐसी सूचना उसकी फर्म विषयक स्थिति का अवधारण करेगी :

परन्तु यदि वह ऐसी सूचना देने में असफल रहता है तो वह उक्त छह मास के अवसान होते ही फर्म में भागीदार हो जाएगा।

(6) जहां कि कोई व्यक्ति एक अप्राप्तवय के तौर पर फर्म की भागीदारी के फायदों में सम्मिलित कर लिया गया है, वहां इस तथ्य को उस व्यक्ति को ऐसे सम्मिलित किए जाने का ज्ञान उसके प्राप्तवय हो जाने से छह मास के अवसान के पश्चात् किसी विशिष्ट तारीख तक नहीं था, साबित करने का भार उस तथ्य का प्राख्यान करने वाले व्यक्तियों होगा।

(7) जहां कि ऐसा व्यक्ति भागीदार हो जाता है, वहां—

(क) अप्राप्तवय के नाते उसके अधिकार और दायित्व उस तारीख तक बने रहते हैं जिस तारीख को वह भागीदार होता है किन्तु वह उन सब फर्म के कार्या के लिए जो भागीदारी के फायदों में उसके सम्मिलित किए जाने के समय से किए गए हैं, पर व्यक्तियों के प्रति वैयक्तिक रूप से दायी भी हो जाता है तथा

(ख) फर्म की संपत्ति और लाभों में उसका अंश वह अंश होगा जिसका वह अप्राप्तवय के तौर पर हकदार था।

(8) जहां कि ऐसा व्यक्ति भागीदार न होने का निर्वाचन करता है, वहां—

- (क) उसके अधिकार और दायित्व उसके द्वारा लोक सूचना दिए जाने की तारीख तक वे ही बने रहेंगे जो अप्राप्तवय के इस धारा के अधीन है:
 - (ख) उसका अंश सूचना की तारीख के पश्चात् किए गए फर्म के किन्हीं भी कार्यों के लिए दायी नहीं होगा: तथा
 - (ग) संपत्ति और लाभों में के अपने अंश के लिए वह भागीदारों पर उपधारा (4) के अनुसार वाद लाने का हकदार होगा।
- (9) उपधारा (7) और (8) की कोई भी बात धारा 28 के उपबन्धों पर प्रभाव न डालेगी।

अध्याय 5

अन्दर आने वाले और बाहर जाने वाले भागीदार

31. भागीदार का प्रविष्ट किया जाना (1) भागीदारों के बीच की संविदा और धारा 30 के उपबन्धों के अधीन यह है कि कोई भी व्यक्ति सब वर्तमान भागीदारों की सम्मति के बिना फर्म में भागीदार के तौर पर प्रविष्ट नहीं किया जाएगा।
- (2) धारा 30 के उपबन्धों के अधीन यह है कि जो व्यक्ति फर्म में भागीदार के तौर पर प्रविष्ट किया गया है तद्द्वारा वह उसके भागीदार होने से पूर्व किए गए किसी भी फर्म के कार्य के लिए दायी नहीं हो जाता।
32. भागीदार का निवृत्त होना –(1) भागीदार –
- (क) अन्य सब भागीदारों की सम्मति से,
 - (ख) भागीदारों के अभिव्यक्त करार के अनुसार, या
 - (ग) जहां की भागीदारी इच्छादीन है, वहां अन्य सब भागीदारों को अपने निवृत्त होने के आशय की लिखित सूचना द्वारा, निवृत्त हो सकेगा।
- (2) निवृत्त होने वाला भागीदार अपने निर्वर्तन से पहले किए गए फर्म के कार्यों के लिए किसी पर व्यक्ति के प्रति किसी दायित्व से ऐसे करार द्वारा, जो ऐसे पर व्यक्ति और पुनर्गठित फर्म के भागीदारों के साथ उसने किया हो, उन्मोचित किया जा सकेगा और ऐसा करार ऐसे पर व्यक्ति को उस निर्वर्तन का ज्ञान होने के पश्चात कि उसके और पुनर्गठित फर्म के बीच की व्यवहार चर्चा से विवक्षित हो सकेगा।

- (3) फर्म से किसी भागीदार से निवृत्ति होने पर भी जब तक कि निवृत्त होने की लोक सूचना न दे दी गई हो, वह और भागीदार उनमें से किसी के द्वारा भी किए गए ऐसे कार्य के लिए, जो उस निर्वतन के पहले किए जाने पर फर्म का कार्य होता, पर व्यक्तियों के प्रति भागीदारों के तौर पर दायी बने रहते हैं

परन्तु निवृत्त भागीदार किसी ऐसे पर व्यक्ति के प्रति दायी नहीं होगा जो फर्म के साथ यह न जानते हुए व्यवहार करता है कि वह भागीदार था।

(4) उपधारा (3) के अधीन सूचनाएं निवृत्त होने वाले भागीदार द्वारा या पुनर्गठित फर्म के किसी भी भागीदार द्वारा दी जा सकेगी।

33. भागीदार का निष्कासन (1) भागीदारों के बीच की संविदा द्वारा प्रदत्त शक्तियों के सद्भावपूर्वक प्रयोग में के सिवाय भागीदार फर्म में से भागीदारों की किसी भी बहुसंख्या द्वारा निष्कासित नहीं किया जा सकेगा।

(2) धारा 32 की उपधाराओं (2), (3) और (4) के उपबन्ध निष्कासित भागीदार को उसी प्रकार लागू होंगे मानो वह निवृत्त भागीदार हो।

34. भागीदार का दिवाला—(1) जहां कि फर्म का कोई भागीदार दिवालिया न्यायनिर्णीत कर दिया जाता है, वहां उस तारीख से जिसको न्यायनिर्णय का आदेश हुआ हो भागीदार नहीं रहेगा चाहे तद्द्वारा फर्म विघटित हो या न हो।

(2) जहां कि किसी भागीदार के दिवालिया न्यायनिर्णीत किए जाने पर फर्म भागीदारों के बीच की संविदा के अधीन विघटित नहीं होती, वहां ऐसी न्यायनिर्णीत भागीदार की सम्पदा फर्म के किसी ऐसे कार्य के लिए और फर्म उस दिवालिया के किसी ऐसे कार्य के लिए दायी नहीं है जो उस तारीख के पश्चात् किया गया हो जिस तारीख को न्यायनिर्णयन का आदेश दिया गया है।

35. मृत भागीदार की सम्पदा का दायित्व – जहां कि किसी भागीदार की मृत्यु द्वारा भागीदारों के बीच की संविदा के अधीन फर्म विघटित नहीं होती, वहां मृत भागीदार को सम्पदा फर्म के किसी ऐसे कार्य के लिए, जो उसकी मृत्यु के पश्चात् किया गया हो, दायी नहीं है।

36. बाहर जाने वाले भागीदार को प्रतियोगी कारबार चलाने का अधिकार—(1) बाहर जाने वाले भागीदार फर्म के कारबार का प्रतियोगी कारबार चला सकेगा, और वह ऐसे कारबार का विज्ञापन कर सकेगा, किन्तु तत्प्रतिकूल संविदा के अधधीन वह —
- (क) फर्म नाम का उपयोग न कर सकेगा।
 - (ख) अपने को फर्म का कारबार चलाने वाला व्यपदिष्ट न कर सकेगा
 - (ग) उन व्यक्तियों से जो उसकी भागीदारी का अन्त हो जाने के पूर्व फर्म से व्यौहार करते थे अपने साथ व्यौहार करने की याचना करेगा।
- (2) व्यापार अवरोधी करार — कोई भागीदार अपने भागीदारों के साथ यह करार कर सकेगा कि भागीदार न रहने पर वह किसी विनिर्दिष्ट कालावधि तक या विनिर्दिष्ट स्थानीय सीमाओं के भीतर फर्म के कारबार के सदृश्य कोईकारबार नहीं चलाएगा और यदि अधिरोपित निर्बन्धन युक्तियुक्त हो, तो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 (1872 का 9) की धारा 27 में किसी बात के होते हुए भी ऐसा करार विधिमान्य होगा।
37. कुछ दशाओं में बाहर जाने वाले भागीदार का पश्चात्वर्ती लाभों में अंश पाने का अधिकार—जहाँ कि फर्म का कोई सदस्य मर गया हो, या अन्यथा भागीदार न रह गया गया हो और उत्तरजीवी या बने रहे भागीदार अपने और बाहर जाने वाले भागीदार या उसकी सम्पदा के बीच लेखाओं का अन्तिम परिनिर्धारण किए बिना फर्म की सम्पत्ति से कारबार चलाते रहें, वहां बाहर जाने वाला भागीदार या उसकी सम्पदा, तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में उक्त भागीदार या उसके प्रतिनिधियों के विकल्प पर या तो उन लाभों का, जो उसके भागीदार न रह जाने के पश्चात् हुए हों ऐसा अंश जो फर्म की सम्पत्ति में के उसके अंश के उपयोग के कारण हुआ माना जा सके या फर्म की सम्पत्ति में के उसके अंश की रकम पर छह प्रतिशत ब्याज पाने की हकदार होगी —:
- परन्तु जहां की भागीदारों के बीच की संविदा के द्वारा उत्तरजीवी या बने रहे भागीदारों को मृत या बाहर जाने वाले भागीदार का हित खरीद लेने का विकल्प किया गया हो और उस विकल्प का सम्यक् रूप से प्रयोग किया गया हो वहां, यथास्थिति, मृत भागीदार की सम्पदा अथवा बाहर वाले भागीदार या उसकी सम्पदा को लाभों का कोई अपर या अन्य अंश पाने का हक न होगा किन्तु यदि कोई

भागीदार उस विकल्प का प्रयोग करने की धारणा से कार्य करते हुए सब तात्त्विक पहलुओं में उसके निबन्धनों का अनुवर्तन न करे तो वह इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों के अधीन लेखा देने का दायी होगा।

38. चलत प्रत्याभूति का फर्म में तब्दीली होने से प्रतिसंहरण फर्म को – फर्म के संव्यवहारों के बारे में परव्यक्ति को दी गई चलत प्रत्याभूति, तत्प्रतिकूल करार के अभाव में, उस तारीख से, जिसको फर्म के गठन में कोई तब्दीली हुई हो, फर्म के भावी संव्यवहारों के बारे में **प्रतिसंहत** हो जाती है।

अध्याय 6

फर्म का विघटन

39. फर्म का विघटन – फर्म के सब भागीदारों के बीच भागीदारी का **विघटन फर्म का विघटन** कहलाता है।
40. करार द्वारा विघटन – फर्म सब भागीदारों की सम्मति से या भागीदारों के बीच की संविदा के अनुसार विघटित की जा सकेगी।
41. वैवश्यक विघटन – फर्म विघटित हो जाती है
- (क) सब भागीदारों के या एक के सिवाय अन्य सब भागीदारों के दिवालिया न्यायनिर्णीत हो जाने से, अथवा
- (ख) किसी ऐसी घटना से घटित होने से जिससे फर्म का कारबार चलना या भागीदारों का उसे भागीदारी में चलाना विधि विरुद्ध हो जाए:
- परन्तु जहां कि फर्म द्वारा एक से अधिक पृथक् प्रोद्यम या उपक्रम चलाए जा रहे हों, वहां किसी एक या अधिक की अवैधता मात्र फर्म के विधिपूर्ण प्रोद्यमों और उपक्रमों के बारे में फर्म का विघटन कारित नहीं करेगी –:
42. किन्हीं आकस्मिकताओं के घटित होने पर विघटन – भागीदारों के बीच की संविदा के अध्यधीन यह है कि फर्म विघटित हो जाती है
- (क) यदि वह किसी नियत अवधि के लिए गठित की गई हो, तो उस अवधि के अवसान से,
- (ख) यदि वह एक या अधिक प्रोद्यमों या उपक्रमों को चलाने के लिए गणित की गई हो तो उसके या उनके पूर्ण हो जाने से,
- (ग) किसी भागीदार की मृत्यु हो जाने से, और
- (घ) किसी भागीदार के दिवालिया न्यायनिर्णीत किए जाने से।

43. इच्छाधीन भागीदारी का सूचना द्वारा विघटन – (1) जहां कि भागीदारी इच्छाधीन है, वहां किसी भागीदार द्वारा फर्म का विघटन अन्य सब भागीदारों को फर्म विघटित करने के अपने आशय की लिखित सूचना दिए जाने द्वारा किया जा सकेगा।
- (2) फर्म उस तारीख से जो उस सूचना में विघटन की तारीख दी हुई है या यदि कोई तारीख नहीं दी हुई है, तो उस तारीख से, जिसको सूचना संसूचित की गई है, विघटित हो जाती है।
44. न्यायालय द्वारा विघटन—' किसी भागीदार के वाद पर न्यायालय निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर फर्म को विघटित कर सकेगा, अर्थात् :-
- (क) यह कि कोई भागीदार विकृतचित हो गया है, जिस दशा में उस व्यक्ति के, जो विकृतचित हो गया है वाद मित्र द्वारा वाद वैसे ही लाया जा सकेगा जैसे किसी दूसरे भागीदार द्वारा:
- (ख) यह कि कोई भागीदार, जो वाद लाने वाले भागीदार से भिन्न हो, भागीदार के तौर पर अपने कर्तव्यों का पालन करने में किसी प्रकार स्थायी रूप से असमर्थ हो गया है:
- (ग) यह कि कोई भागीदार जो वाद लाने वाले भागीदार से भिन्न हो, ऐसे आचरण का दोषी है जिससे कारबार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उस कारबार के चलाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता सम्भाव्य है:
- (घ) यह कि कोई भागीदार, जो वाद लाने वाले भागीदार से भिन्न हो, ऐसे करारों का भंग जानबूझकर या बार-बार करता है जो फर्म के कामकाज के प्रबन्ध या फर्म के कारबार के संचालन से संबंधित हों या अन्यथा उस कारबार के सम्बन्धित बातों में ऐसा अपना आचरण रखता है कि उसके साथ भागीदारों में वह कारबार करना दूसरे भागीदारों के लिए युक्तियुक्ततः साध्य नहीं है
- (ङ) यह कि किसी भागीदार ने, जो वाद लाने वाले भागीदार से भिन्न हो, फर्म में का अपना सम्पूर्ण हित किसी पर-व्यक्ति को किसी प्रकार से अन्तरित कर दिया है, या अपने अंश को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुसूची के आदेश 21 के नियम 49 के अधीन भारत हो जाने दिया है अथवा अपना द्वारा शोध्य भू-राजस्व की बकाया की या

भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय किन्हीं शोध्यों की वसूली में बिक जाने दिया है।

(च) यह कि फर्म का कारोबार हानि उठाए बिना नहीं चलाया जा सकता: अथवा

(छ) किसी अन्य ऐसे आधार पर, जिसने इस बात को न्यायसंगत और साम्यपूर्ण बना दिया हो कि फर्म विघटित कर दी जाए।

- 45- विघटन के पश्चात् किए गए भागीदारों के कार्यों के लिए दायित्व (1) फर्म का विघटन हो जाने पर भी जब तक विघटन की लोक सूचना न दे दी जाए भागीदार उनमें से किसी के द्वारा किए गए किसी ऐसे कार्य के लिए जो विघटन से पहले किया जाने पर फर्म का कार्य होता पर-व्यक्तियों के प्रति भागीदार के नातेदायी बने रहेंगे:

परन्तु जो भागीदार मर जाता है या दिवालिया न्यायनिर्णीत कर दिया जाता है, या जो भागीदार, उसका भागीदार होना फर्म के साथ व्यवहार करने वाले व्यक्ति को ज्ञात न होते हुए, फर्म से निवृत्त हो जाता है, उसकी सम्पदा उसके भागीदार न रहने की तारीख के पश्चात् किए गए कार्यों के लिए इस धारा के अधीन दायी न होगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन सूचनाएं किसी भी भागीदार द्वारा दी जा सकेंगी।

46. विघटन के पश्चात् कारबार का परिसमापन कराने का भागीदारों का अधिकार – फर्म के विघटन पर हर भागीदार या उसके प्रतिनिधि को अन्य सब भागीदारों या उनके प्रतिनिधियों के विरुद्ध यह हक है कि वह फर्म की सम्पत्ति को फर्म के ऋणों और दायित्वों के संदाय में उपयोजित कराए और अधिशेष को भागीदारों या उनके प्रतिनिधियों में उनके अधिकारों के अनुसार वितरित कराए।

47. परिसमपान के प्रयोजनों के लिए भागीदारों का सतत प्राधिकार – हर एक भागीदार का फर्म को आबद्ध करने का प्राधिकार और भागीदारों के अन्य पारस्परिक अधिकार और बाध्यताएं फर्म का विघटन हो जाने पर भी फर्म के विघटन के पश्चात् वहां तक बने रहते हैं जहां तक कि वे फर्म के कामकाज के परिसमापन के लिए और आरम्भ किए गए किन्तु विघटन के समय अधूरे रह गए संव्यवहारों को पूरा करने के लिए आवश्यक हों, किन्तु अन्यथा नहीं

परन्तु फर्म किसी ऐसे भागीदार के कार्यों के द्वारा, जो दिवालिया न्यायनिर्णीत कर दिया गया है, किसी दशा में भी आबद्ध नहीं है किन्तु यह परन्तुक किसी ऐसे

व्यक्ति के दायित्व पर प्रभाव नहीं डालता जिसने उस न्यायनिर्णयन के पश्चात् अपने को इस दिवालिया का भागीदार होना व्यपदिष्ट किया है या जानते हुए व्यपदिष्ट किया जाने दिया है।

48. भागीदारों के बीच लेखा परिनिर्धारण का ढंग – विघटन के पश्चात् फर्म के लेखा परिनिर्धारण में भागीदारों द्वारा किए गए करार के अध्यक्षीन, निम्नलिखित नियमों का अनुपालन किया जाएगा—

(क) हानियां जिनके अन्तर्गत पूंजी की कमियां भी आती हैं, प्रथमतः लाभों में से तत्पश्चात् पूंजी में से और अन्त में, यदि आवश्यक हो, भागीदारों द्वारा व्यष्टितः उसी अनुपात में संदत्त की जाएगी जिनमें वे लाभों का अंश पाने के लिए हकदार थे,

(ख) फर्म की आस्तियां जिनके अंतर्गत पूंजी की कमी को पूरा करने के लिए भागीदारों द्वारा अभिदत्त की गई रकम भी आती है, निम्नलिखित प्रकार और क्रम से उपयोजित की जाएंगी —:

- (1) फर्म पर—व्यक्तियों के ऋणों का संदाय करने में
- (2) हर एक भागीदार को फर्म द्वारा उसे शोध्य उन अभिदायों का जो पूंजी से सुभिन्न हों, अनुपाती संदाय करने में
- (3) हर एक भागीदार को पूंजी लेखे जो शोध्य हो उसका अनुपाती संदाय करने में तथा
- (4) अवशिष्ट, यदि कुछ रहे, तो वह भागीदारों में उस अनुपात में जिसमें वे लाभों का अंश पाने के हकदार थे, बांट दिया जाएगा।

49. फर्म के ऋणों और पृथक् ऋणों का संदाय – जहां कि फर्म द्वारा शोध्य संयुक्त ऋण हैं और किसी भागीदार द्वारा शोध्य पृथक् ऋण भी है, वहां फर्म की सम्पत्ति का उपयोजन प्रथमतः फर्म के ऋणों के संदाय में किया जाएगा और यदि कुछ अधिशेष रहे तो उसमें का हर एक भागीदार का अंश उसके पृथक् ऋणों के संदाय में उपयोजित किया जाएगा या उसको दे दिया जाएगा। किसी भी भागीदार की पृथक् सम्पत्ति का उपयोजन पहले उसके पृथक् ऋणों के संदाय में और, यदि कुछ अधिशेष रहे, तो फर्म के ऋणों के संदाय में किया जाएगा।

50. विघटन के पश्चात् उपार्जित वयक्तिक लाभ – भागीदारों बीच की संविदा के अध्यक्षीन यह है कि धारा 16 के खंड (क) के उपबन्ध उन संव्यवहारों को लागू

होंगे जिनका उपक्रम किसी भागीदार की मृत्यु के कारण फर्म का विघटन हो जाने के पश्चात् और उसके सब कामकाज का पूर्ण रूप से परिसमापन होने के पूर्व, किसी उत्तरजीवी भागीदार द्वारा या किसी मृत भागीदार के प्रतिनिधियों द्वारा किया गया हो :

परन्तु जहां कि किसी भागीदार या उसके प्रतिनिधि ने फर्म का गुडविल खरीद लिया है, वहां इस धारा की कोई भी बात फर्म या नाम के उपयोग में लाने के उसके अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

51 समयपूर्व विघटन में प्रीमियम की वापसी – जहां कि किसी भागीदार ने भागीदारी में किसी नियत अवधि के लिए प्रवेश करते समय कोई प्रीमियम दिया है और उस अवधि का अवसान होने के पूर्व ही वह फर्म किसी भागीदार की मृत्यु के सिवाय किसी अन्य कारण से, विघटित हो जाती है, वहां वह भागीदार उस प्रीमियम के या उसके ऐसे भाग का प्रतिसंदाय पाने का हकदार होगा जो उन निबन्धनों को, जिन पर वह भागीदार बना था, और उस समय की लम्बाई को जिनके दौरान वह भागीदार रहा, ध्यान में रखते हुए युक्तियुक्त हों, जब तक कि—

(क) विघटन मुख्यतया उनके अपने अवचार के कारण न हुआ हो अथवा

(ख) विघटन ऐसे करार के अनुसरण में न हुआ जिसमें उस प्रीमियम या उसके किसी भाग के वापस करने के विषय में कोई उपबन्ध अन्तर्विष्ट नहीं है।

52. अधिकार, जहां कि भागीदारों की संविदा, कपट या दुर्व्यपदेशन के कारण विखंडित कर दी गई है—जहां भागीदारी सृष्ट करने वाली संविदा उसके पक्षकारों में से किसी के कपट या दुर्व्यपदेशन के आधार पर विखण्डित कर दी जाती है, वहां विखण्डित करने का हक रखने वाला पक्षकार अन्य किसी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित का हकदार होगा।

(क) फर्म के अंश क्रय करने के निमित्त अपने द्वारा दी गई किसी राशि के लिए और अपने द्वारा अभिदत्त किसी पूंजी के लिए फर्म के उस अधिशेष या आस्तियों पर, जो फर्म के ऋणों के संदाय के पश्चात् अवशिष्ट हों, धारणाधिकार का या उनके प्रतिधारण के अधिकार का,

(ख) फर्म के ऋणों मद्धे अपने द्वारा किए गए किसी संदाय के बारे में फर्म के लेनदारों की पंक्ति में रखे जाने का तथा

(ग) फर्म के सब ऋणों की बाबत क्षतिपूर्ति उस भागीदार या उन भागीदारों से पाने का जो उस कपट या दुर्व्यपदेशन के दोषी हों।

53. फर्म नाम या फर्म की सम्पत्ति को उपयोग में लाने में अवरुद्ध करने का अधिकार – फर्म के विघटित हो जाने के पश्चात् हर भागीदार या उसका प्रतिनिधि, भागीदारों के बीच की किसी तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में, किसी भी अन्य भागीदार को या उसके प्रतिनिधि को, तब तक के लिए फर्म नाम से समरूप कारबार करने से या फर्म की किसी सम्पत्ति को अपने निजी फायदे के लिए उपयोग में लाने से अवरुद्ध कर सकेगा, जब तक फर्म के कामकाज का पूरी तरह परिसमपान नहीं हो जाता:

परन्तु जहां कि किसी भागीदार या उसके प्रतिनिधि ने फर्म का गुडविल खरीद लिया है, वहां इस धारा की कोई भी बात फर्म नाम को उपयोग में लाने के उसके अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

54. व्यापार अवरुद्धी करार – फर्म के विघटन पर या विघटन के पूर्वानुमान पर भागीदार यह करार कर सकेंगे कि उनमें से कुछ या वे सब किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के या विनिर्दिष्ट स्थानीय सीमाओं के भीतर फर्म के कारबार के सदृश्य कारबार नहीं चलाएंगे और यदि अधिरोपित निर्बन्धन युक्तियुक्त हों, तो भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का 9) की धारा 27 में किसी बात के होते हुए भी ऐसा करार विधिमान्य होगा।

55. विघटन के पश्चात् गुडविल का विक्रय (1) विघटन के पश्चात् फर्म के लेखा परिनिर्धारण में गुडविल, भागीदारों के बीच की संविदा के अध्यक्षीन रहते हुए आस्तियों में सम्मिलित किया जाएगा और वह या तो पृथक् रूप से या फर्म की अन्य सम्पत्ति के साथ साथ बेचा जा सकेगा।

(2) गुडविल के क्रेता और विक्रेता के अधिकार – जहां कि फर्म का गुडविल विघटन के पश्चात् बेचा जाता है, वहां भागीदार क्रेता के कारबार का प्रतियोगी कारबार चला सकेगा और वह ऐसे कारबार का विज्ञापन कर सकेगा, किन्तु अपने और क्रेता के बीच के करार के अध्यक्षीन वह निम्नलिखित न कर सकेगा

(क) फर्म नाम का उपयोग में लाना

(ख) यह व्यपदिष्ट करना कि वह फर्म का कारबार चला रहा है, अथवा

- (ग) जो व्यक्ति फर्म के विघटन से पूर्व फर्म से व्यवहार करते थे उनमें अपने साथ व्यवहार करने की याचना।
- (3) व्यापार अवरोधी करार – कोई भी भागीदार फर्म के गुडविल के विक्रय पर क्रेता से यह करार कर सकेगा कि ऐसा भागीदार किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के या स्थानीय सीमाओं के भीतर फर्म के कारबार के सदृश्य कोई कारबार नहीं चलाएगा, और यदि अधिरोपित निर्बन्धन युक्तियुक्त हो तो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 (1872 का 9) की धारा 27 में किसी बात के होते हुए भी ऐसा करार विधिमान्य होगा।

अध्याय 7

फर्मों का रजिस्ट्रीकरण

56. इस अध्याय के लागू होने से छूट देने की शक्ति—किसी राज्य की राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि इस अध्याय के उपबन्ध उस राज्य को या उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट उसके किसी भाग को लागू नहीं होंगे।
57. रजिस्ट्रारों की नियुक्ति (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए फर्मों के रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी और उन क्षेत्रों को परिभाषित कर सकेगी जिनमें वे अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे।
- (2) हर रजिस्ट्रार भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा।
58. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन (1) फर्म का रजिस्ट्रीकरण उस क्षेत्र के रजिस्ट्रार को, जिसमें उस फर्म के कारबार का कोई स्थान स्थित है या स्थित किया जाना प्रस्थापित है, विहित प्ररूप में और विहित फीस ऐसा कथन जिसमें निम्नलिखित कथित हो, डाक द्वारा भेज कर या परिदत्त करके किसी भी समय कराया जा सकेगा।
- (क) फर्म का नाम
 - (ख) फर्म के कारबार का स्थान या मुख्य स्थान
 - (ग) उन अन्य स्थानों के नाम जिनमें फर्म कारबार चलाती है
 - (घ) वह तारीख जिसको हर एक भागीदार फर्म में शामिल हुआ
 - (ङ) भागीदारों के पूरे नाम और स्थायी पते तथा

(च) फर्म की अस्तित्वावधि

यह कथन सब भागीदारों द्वारा या उनके ऐसे अभिकर्ताओं द्वारा जो इस निमित्त विशेषतया प्राधिकृत हों हस्ताक्षरित किया जाएगा

(2) कथन को हस्ताक्षरित करने वाला हर एक व्यक्ति विहित प्रकार से उसे सत्यापित भी करेगा।

(3) फर्म नाम में निम्नलिखित शब्दों में से किसी का भी अर्थात् –

‘क्राउन’, ‘एम्परर’, ‘एम्प्रेस’, ‘एम्पायर’, ‘एम्पीरियल’, ‘किंग’, ‘क्वीन’, ‘रायल’, या ऐसे शब्दों का, जिनसे सरकार को मंजूरी, अनुमोदन या प्रतिश्रय अभिव्यक्त या विवक्षित होता हो, उपयोग न किया जाएगा सिवाय जब कि राज्य सरकार ने फर्म नाम के भाग स्वरूप ऐसे शब्दों के उपयोग के लिए अपनी सम्मति लिखित आदेश द्वारा दे दी हो।

59. रजिस्ट्रीकरण—जब कि रजिस्ट्रार का समाधान हो जाए कि धारा 58के उपबन्धों का सम्यक् रूप से अनुवर्तन हो गया है, तब वह फर्मों का रजिस्ट्रार नामक रजिस्टर में उस कथन की प्रविष्टि अभिलिखित करेगा और उस कथन को फाइल कर देगा।

60. फर्म नाम में और कारबार में मुख्य स्थान में हुए परिवर्तनों का अभिलेख—(1) जब कि किसी रजिस्ट्रीकृत फर्म के फर्म नाम में या कारबार के मुख्य स्थान की स्थिति में कोई परिवर्तन किया जाएगा, तब विहित फीस के साथ रजिस्ट्रार के पास एक ऐसा कथन भेजा जा सकेगा जिसमें उस परिवर्तन का विनिर्देश हो और जो धारा 58 के अधीन अपेक्षित प्रकार के हस्ताक्षरित और सत्यापित हो।

(2) जब कि रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाए कि उपधारा (1) के उपबन्धों का सम्यक् रूप से अनुवर्तन हो गया है तब वह फर्म रजिस्टर में उस फर्म संबंधी प्रविष्टि को उस कथन के अनुसार संशोधित करेगा और धारा 59 के अधीन फाइल किए गए फर्म संबंधी कथन के साथ उसे फाइल कर देगा।

61. शाखाओं के बन्द करने और खोलने का टिप्पणित किया जाना— जब कि कोई रजिस्ट्रीकृत फर्म किसी ऐसे स्थान पर अपना कारबार बन्द या चलाना आरम्भ करे जो उसके कारबार का मुख्य स्थान न हो तब उस फर्म का कोई भी भागीदार या अभिकर्ता उसकी प्रज्ञापन रजिस्ट्रार को भेज सकेगा या जो फर्म रजिस्टर में उस फर्म सम्बन्धी प्रविष्टि में ऐसी प्रज्ञापना का टिप्पणन करा लेगा और धारा 59 के अधीन फाइल किए गए फर्म संबंधी कथन के साथ उस प्रज्ञापन को फाइल कर देगा।

62. भागीदारों के नामों और पतों में तब्दीलियों का टिप्पणित किया जाना—जब कि रजिस्ट्रीकृत फर्म का कोई भागीदार अपने नाम या स्थायी पते में कोई परिवर्तन करे, तब फर्म के किसी भी भागीदार या अभिकर्ता द्वारा रजिस्ट्रार को उस परिवर्तन की प्रज्ञापना भेजी जा सकेगी और रजिस्ट्रार उससे उसी प्रकार बरतेगा जैसा धारा 61 में उपबन्धित है।
63. फर्म में तब्दीलियों और उसके विघटन का अभिलेखन—(1) जब कि किसी रजिस्ट्रीकृत फर्म के गठन में कोई तब्दीली हो तब अन्दर जाने वाला, बना रहने वाला या बाहर जाने वाला कोई भी भागीदार और जबकि किसी रजिस्ट्रीकृत फर्म का विघटन हो, तब कोई भी व्यक्ति, जो विघटन से अव्यवहित पहले भागीदार रहा हो, या किसी भी भागीदार या व्यक्ति का इस निमित्त विशेषतया प्राधिकृत अभिकर्ता रजिस्ट्रार को ऐसी तब्दीली या विघटन की तारीख का विनिर्देश करते हुए उसकी सूचना देगा और रजिस्ट्रार फर्मों के रजिस्टर में उस फर्म संबंधी प्रविष्टि में उस सूचना का अभिलेखन करेगा और सूचना के धारा 59 के अधीन फाइल किए गए फर्म संबंधी कथन के साथ फाइल कर देगा।
- (2) अप्राप्तवय के प्रत्याहरण का अभिलेखन—जब कि कोई अप्राप्तवय जो किसी फर्म में भागीदारी के फायदों में सम्मिलित कर लिया गया हो, प्राप्तवय हो जाए और भागीदार बनाने का या न बनाने का निर्वाचन कर ले और फर्म उस समय रजिस्ट्रीकृत फर्म हो तब वह या इस निमित्त विशेषतया प्राधिकृत उसका अभिकर्ता रजिस्ट्रार को यह सूचना दे सकेगा कि वह भागीदार बन गया है या नहीं बना है और रजिस्ट्रार उस सूचना से उसी प्रकार बरतेगा जैसा उपधारा (1) में उपबन्धित है।
64. भूलों का परिशोधन—(1) रजिस्ट्रार को यह शक्ति हर समय होगी कि फर्मों के रजिस्टर में की किसी प्रविष्टि को जो किसी भी फर्म के संबंधित हो इस अध्याय के अधीन फाइल की गई उस फर्म संबंधी दस्तावेजों के अनुरूप बनाने के लिए किसी भी भूल का परिशोधन करे।
- (2) उन सब पक्षकारों के आवेदन पर जिन्होंने इस अध्याय के अधीन फाइल की गई फर्मों संबंधी किसी दस्तावेज को हस्ताक्षरित किया है, रजिस्ट्रार में किये गए उसके अभिलेख या टिप्पणी में हो।
65. न्यायालय के आदेश से रजिस्टर संशोधन—रजिस्ट्रीकृत फर्म से संबंधित किसी भी मामले का विनिश्चय करने वाला न्यायालय यह निदेश दे सकेगा कि रजिस्ट्रार फर्मों के रजिस्टर में ऐसी फर्म से संबंधित प्रविष्टि में ऐसा कोई भी संशोधन करे, जो उसके विनिश्चय के परिणामस्वरूप और रजिस्ट्रार तदनुसार उस प्रविष्टि का संशोधन करेगा।

66. रजिस्टर और फाइल की गई दस्तावेजों का निरीक्षण—(1) फर्मों का रजिस्टर, ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए, किसी भी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रहेगा।
(2) इस अध्याय के अधीन फाइल किए गए सब कथन, सूचनाएं और प्रज्ञापनाएं ऐसी शर्तों के अधीन और ऐसी फीस के संदाय पर, जैसी विहित की जाए, निरीक्षण के लिए खुला रहेगा।
67. प्रतियों का दिया जाना—किसी भी व्यक्ति को उसके आवेदन पर रजिस्ट्रार ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की गई हो, फर्म के रजिस्टर में कि किसी भी प्रविष्टि या किसी उसके किसी भी भाग की अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित प्रति देगा।
68. साक्ष्य के नियम—(1) फर्मों का रजिस्टर में अभिलिखित या टिप्पणित कोई भी कथन प्रज्ञापना या सूचना उसमें कथित किसी भी तथ्य का निश्चयक सबूत उस व्यक्ति के विरुद्ध होगी, जिसके द्वारा या जिसकी ओर से ऐसा कथन, प्रज्ञापना या सूचना हस्ताक्षरित की गई थी।
(2) फर्मों के रजिस्टर में की किसी फर्म से संबंधित किसी भी प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति उस फर्म के रजिस्ट्रीकरण के तथ्य के तथा उसमें अभिलिखित या टिप्पणित किसी भी कथन, प्रज्ञापना या सूचना की अन्तर्वस्तु के सबूत में पेश की जा सकेगी।
69. रजिस्ट्री न कराने का प्रभाव— (1) कोई भी वाद जो किसी संविदा से उद्भूत या इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी अधिकार को प्रवृत्त कराने के लिए लाया जाए किसी फर्म के भागीदार के नाते वाद लाने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा या की ओर से उस फर्म के विरुद्ध या किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जिसका उस फर्म में भागीदार होना या रहा होना अभिकथित हो, किसी भी न्यायलय में संस्थित नहीं किया जाएगा जब तक कि वह फर्म रजिस्ट्रीकृत न हो ओर वाद लाने वाला व्यक्ति फर्मों के रजिस्टर में उस फर्म के भागीदार के तौर पर दर्शित न हो या दर्शित न रह चुका हो।
(2) कोई भी वाद जो किसी संविदा से उद्भूत किसी अधिकार को प्रवृत्त कराने के लिए लाया जाए फर्म द्वारा या की ओर से किसी भी न्यायलय में किसी पर—व्यक्ति के विरुद्ध संस्थित न किया जाएगा जब तक कि वह फर्म रजिस्ट्रीकृत न हो और वाद लाने वाले व्यक्ति फर्मों के रजिस्टर में फर्म के भागीदारों के तौर पर दर्शित न हों या दर्शित न रह चुके हों।

(3) उपधाराओं (1) और (2) के उपबन्ध किसी संविदा में उद्भूत किसी अधिकार को प्रवृत्त कराने के लिए लाए जाने वाली मुजराई के दावे या अन्य कार्यवाई को भी लागू होंगे, किन्तु निम्नलिखित पर प्रभाव न डालेंगे,—

(क) किसी फर्म के विघटन के लिए या किसी विघटित फर्म का लेखा लेने के लिए, वाद लाने के किसी अधिकार के या किसी विघटित फर्म की सम्पत्ति प्राप्त करने के किसी भी अधिकार या शक्ति के प्रवर्तन पर, अथवा

(ख) किसी दिवालिया भागीदार की सम्पत्ति को प्राप्त करने की किसी शासकीय समनुदेशिती, रिसेवर या न्यायलय की प्रेसीडेंसी नगर दिवाला अधिनियम, 1909 (1909 का 3) या प्रान्तीय दिवाला अधिनियम, 1920 (1920 का 5) के अधीन शक्तियों पर।

(4) यह धारा निम्नलिखित को लागू न होगी—

(क) ऐसी फर्मों को या फर्मों के भागीदारों को, जिनके कारबार का कोई स्थान जिनपर इस अधिनियम का विस्तार है, या जिनके कारबार के स्थान उक्त राज्य क्षेत्रों के ऐसे क्षेत्रों में स्थित हैं जिनको धारा 56 के अधीन की गई अधिसूचना के कारण यह अध्याय लागू नहीं है, अथवा

(ख) मूल्य में सौ रूपए से अनधिक के किसी भी ऐसे वाद या मुजराई के दावे को, जो प्रेसिडेंसी नगरों में प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायलय अधिनियम, 1882 (1882 का 15) की धारा 19 में विनिर्दिष्ट किस्म का, या प्रेसिडेंसी नगरों के बाहर प्रान्तीय लघुवाद न्यायलय अधिनियम, 1887 (1887 का 8) की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किस्म का न हो अथवा निष्पादन में कि किसी भी कार्यवाही या अन्य कार्यवाही को जो ऐसे वाद या दावे से आनुषंगिक या उद्भूत हो।

70. मिथ्या विशिष्टियां देने के लिए शास्ति—कोई भी व्यक्ति जो इस अध्याय के अधीन किसी ऐसे कथन, संशोधक—कथन, सूचना या प्रज्ञापना को हस्ताक्षरित करेगा, जिसमें कोई ऐसी विशिष्टि अन्तर्विष्ट है, जिसका मिथ्या होना वह जानता है, या जिसके सत्य होने का वह विश्वास नहीं करता अथवा जिसमें ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट हैं जिनका अपूर्ण होना वह जानता है या जिनके पूर्ण होने का वह विश्वास नहीं करता वह कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।

71. नियम बनाने की शक्ति—राज्य सरकार, राजजत्र में अधिसूचना, द्वारा ऐसे नियम लाना सकेगी जो वह फीस विहित करेंगे जो फर्म के रजिस्ट्रार को भेजी जाने वाली दस्तावेजों के साथ भेजी जाएगी या उन दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए, जो फर्मों के रजिस्ट्रार की अभिरक्षा में हों या फर्मों के रजिस्टर में की प्रतियों के लिए संदेय होगी।

परन्तु ऐसी फीसें अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट अधिकतम फीसों से अधिक न होंगी।

(2) राज्य सरकार ऐसे नियम भी बना सकेगी जो—

- (क) धारा 58 के अधीन दिए जाने वाले कथन और उसके सत्यापन का प्ररूप विहित करेंगे,
 - (ख) यह अपेक्षित करेंगे कि धाराओं 60,61,62, और 63 के अधीन कथन, प्रज्ञापनाएँ और सूचनाएं विहित प्ररूप में हों और उनका प्ररूप विहित करेंगे,
 - (ग) फर्मों के रजिस्टर का प्ररूप और वह ढंग जिस ढंग से फर्मों सम्बन्धी प्रविष्टियां उसमें की जानी हैं तथा वह ढंग जिस ढंग से ऐसी प्रविष्टियां संशोधित की जानी हैं, या उनमें टिप्पण किए जाने हैं, विहित करेंगे,
 - (घ) विवादों के उद्भूत होने पर रजिस्ट्रार द्वारा अनुवर्तनीय प्रक्रिया विनियमित करेंगे,
 - (ङ) रजिस्ट्रार द्वारा प्राप्त दस्तावेजों का फाइल किया जाना विनियमित करेंगे,
 - (च) मूल दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए, शर्तें विहित करेंगे,
 - (छ) प्रतियों का दिया जाना विनियमित करेंगे
 - (ज) रजिस्ट्रारों और दस्तावेजों की छंटाई विनियमित करेंगे,
 - (झ) फर्मों के रजिस्टर की अनुक्रमणिका का रखा जाना और उसका प्ररूप उपबन्धित करेंगे, तथा
 - (ञ) साधारणतया इस अध्याय के प्रयोजनों के कार्यान्वित करने के लिए होंगे।
- (3) इस धारा के अधीन बनाए गए सब नियम पूर्व प्रकाशन की शर्त की अध्याधीन होंगे।
- (4) इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने पर यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा।

अध्याय 8

अनुपूरक

72. लोक सूचना देने का ढंग—इस नियम के अधीन लोक सूचना—

- (क) जहाँ कि वह, किसी रजिस्ट्रीकृत फर्म से किसी भागीदारी की निवृत्ति या निष्कासन से या किसी रजिस्ट्रीकृत फर्म में ऐसे व्यक्ति के जिसे भागीदार के फाइदे के या निष्कासन से, या किसी रजिस्ट्रीकृत फर्म के विघटन से या किसी रजिस्ट्रीकृत फर्म में ऐसे व्यक्ति के, जिसे भागीदार के फायदों में अप्राप्तवय के तौर पर सम्मिलित कर लिया गया था प्राप्त वय होने पर भागीदार बन जाने के या न बनने के निर्वाचित से, सम्बन्धित है, वहाँ फर्मों के रजिस्ट्रार को धारा 63 के अधीन सूचना देकर और शासकीय राजपत्र में और देशी भाषा के कम से कम एक ऐसे समाचार-पत्र में, जिसका परिचालन उस जिले में हो, जिसमें उस फर्म का जिससे वह सूचना सम्बन्धित है, कारबार का स्थान या मुख्य स्थान है, प्रशासन द्वारा दी जाती है तथा
- (ख) किसी भी अन्य दशा में, शासकीय राजपत्र में और देशी भाषा के कम से कम एक ऐसे समाचार-पत्र में जिसका परिचालन उस जिले में हो, जहाँ फर्म के कारबार का स्थान का मुख्य स्थान है, प्रकाशन, द्वारा दी जाती है।

73. निरसन अधिनियम 1938 (1938 का 1) की धारा 2 तथा अनुसूची द्वारा निरसित।
74. व्यावृत्तियाँ—इस अधिनियम की या एतद् द्वारा किए गए किसी निरसन में कोई भी बात निम्नलिखित पर प्रभाव न डालेगी। ओर न प्रभाव डालने वाली समझी जाएगी—
- (क) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पहले ही अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत कोई भी अधिकार, हक, हित, वाध्यता या दायित्व, अथवा
- (ख) ऐसे किसी भी अधिकार, हक, हित, वाध्यता या दायित्व के बारे में या किसी भी ऐसी बात के बारे में जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व की गई या सहन की गई हो, कोई विधिक कार्यवाही या उपचार, अथवा
- (ग) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व की गई या सहन की गई कोई भी बात, अथवा
- (घ) भागीदारी सम्बन्धी कोई भी अधिनियमित जो इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त रूप से निरसित नहीं की गई है, अथवा
- (ङ) भागीदारी से सम्बन्धित दिवाले का कोई भी नियम, अथवा
- (च) विधि का कोई भी नियम जो इस अधिनियम से असंगत न हो।

(अनुसूची 1 अनुसूची 2)

अनुसूची 1

अधिकतम फीस

धारा 71 की उपधारा (1) देखिए

धारा 58 के अधीन कथन	तीन रूपए
धारा 60 के अधीन कथन	एक रूपए
धारा 61 के अधीन प्रज्ञापना	एक रूपया
धारा 62 के अधीन प्रज्ञापना	एक रूपया
धारा 63 के अधीन प्रज्ञापना	एक रूपया
धारा 64 के अधीन आवेदन	एक रूपया
धारा 66 की उपधारा (1) के अधीन फर्मों के रजिस्टर का निरीक्षण	रजिस्टर की एक जिल्द के निरीक्षण के लिए आठ आना।
धारा 66 की उपधारा (2) के फर्मों के संबंधी दस्तावेजों का निरीक्षण	एक फर्म से संबंधित, समस्त, दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए आठ आना।
फर्मों के रजिस्टर में से प्रतियां	प्रति सौ शब्द या उसके भाग के लिए चार आना।
अनुसूची 2 निरसन अधिनियम, 1938 (1938 का 1) की धारा 2 तथा अनुसूची द्वारा निरसित।	

**THE INDIAN PARTNERSHIP
ACT 1932.**

CONTENTS

CHAPTER - I

PRELIMINARY

Sections	Pages
1. Short title, extent and commencement	1
2. Definitions	1
3. Application of provisions of Act 9 of 1872	1

**CHAPTER - II
THE NATURE OF PARTNERSHIP**

4. Definition of " Partnership", "Partner", "Firm" and "firm name" ..	1
5. Partnership not created by status 1	
6. Mode of determining existence of partnership	2
7. Partnership at will	2
8. Particular partnership	2

**CHAPTER - III
RELATIONS OF PARTNERS TO ONE ANOTHER**

9. General duties of partners	2
10. Duty to indemnify for loss caused by fraud	2
11. Determination of rights and duties of partners by contract between the partners.	2
12. The conduct of the business	3
13. Mutual rights and liabilities	3
14. The property of the firm.	3
15. Application of the property of the firm	3
16. Personal profits named by partners	4
17. Rights and duties of partners	4

**CHAPTER - IV
RELATION OF PARTNERS TO THIRD PARTIES**

18. Partners to be agent of the firms	4
19. Implied authority of partner as agent of the firm	4

20.	Extension and restriction of partner's implied authority.	5
21.	Partner's authority in an emergency	5
22.	Mode of doing act to bind firm	5
23.	Effect of admissions by a partner	5
24.	Effect of notice to acting partner	5
25.	Liability of a partner for acts of the firm	5
26.	Liability of the firm for wrongful acts of a partner.	5
27.	Liability of firm for misapplication by partners	5
28.	Holding out	5
29.	Rights of transferee of a partner's interest	5
30.	Minors admitted to the benefits of partnership.	

CHAPTER - V INCOMING AND OUTGOING PARTNERS.

31.	Introduction of a partner	7
32.	Retirement of a partner	7
33.	Expulsion of a partner	7
34.	Insolvency a partner	7
35.	Liability of estate of deceased partner	8
36.	Rights of outgoing partner to carry on competing business	8
37.	Right of outgoing partner in certain cases to share subsequent profits	8
38.	Revocation of continuing guarantee by change in firm	8

CHAPTER -VI DISSOLUTION OF A FIRM

39.	Dissolution of firm	8
40.	Dissolution by agreement	8
41.	Compulsory dissolution	8
42.	Dissolution on the happening of certain contingencies	9
43.	Dissolution by notice of partnership at will	9
44.	Dissolution by the	
45.	Liability for acts of partners done after dissolution	10
46.	Right of partners to have business wound up after dissolution.	10
47.	Continuing authority of partners for purposes of winding up	10
48.	Mode of settlement of accounts between partners	10
49.	Payment of firm debts and of separate debts.	11
50.	Personal profits earned after dissolution	11

51.	Return of premium on premature dissolution	11
52.	Rights where partnership contract is rescinded for fraud or misrepresentation	11
53.	Rights to restrain from use of firm name or firm property	11
54.	Agreements in restraint of trade	12
55.	Sale of good will after dissolution	12

**CHAPTER - VII
REGISTRATION OF FIRMS**

56.	Power to exempt from application of this Chapter	12
57.	Appointment of Registrar	12
58.	Application of registration	12
59.	Registration	13
60.	Recording of alterations in firm name and principal place of business.	13
61.	Noting of closing and opening of branches	13
62.	Noting of changes in names and addresses of partners	13
63.	Recording of changes in and dissolution of a firm	13
64.	Rectification of mistakes	14
65.	Amendment of Register by order of court	14
66.	Inspection of Register and filed documents	14
67.	Grant of copies	14
68.	Rules of evidence	14
69.	Effect of non- registration	14
70.	Penalty for furnishing of false particulars	15
71.	Power to make rules	15

**CHAPTER - VIII
SUPPLEMENTAL**

72.	Mode of giving public notice	16
73.	[Repeals]	16
74.	Saving	16

THE INDIAN PARTNERSHIP ACT , 1932.
(ACT NO.9 OF 1932)

(8th April,1932)

An Act to define and amend the law relating to partnership.

WHEREAS it is expedient to define and amend the law relating to partnership, It is hereby an acted as follows:

CHAPTER - I- PRELIMINARY

1. **Short title extend and commencement** - (1) This Act may be called the Indian partnership Act. 1932.
 2. It extends to the whole of India except the State of Jammu & Kashmir.
 3. It shall come into force on the 1st day of October , 1932, except Sec. 69 which shall come into force on the 1st day October, 1933.

2. **Definitions** - In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context -
 - a) An " act of a firm" means any act or omission by all the partners, or by any partner or agent of the firm which gives rise to a right enforceable by or against the firm":
 - b) " business" includes every trade, occupation and profession.
 - c) "Prescribed" means prescribed by rules made under this Act"
 - d) "Thirdy party " used in relation to a firm or to a partner therein means any person who is not a partner in the firms" and
 - e) expression used but not defined in this Act and defined in the Indian

3. **Application of provisions of Act 9 of 1872** - The unrepealed provisions of the Indian contract Act, 1872 , save in so far as they are inconsistent with the express provision of this act, shall continue to apply to firms

CHAPTER - II - THE NATURE OF PARTNERSHIP

4. **Definition of " Partnership", "partner", firm" and "firm name"**- "Partnership" is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all.

Persons who have entered into partnership with one another are called individually "partners" and collectively "a firm", and the name under which their business is carried on is called the "firm name"

Short Note'

-Sec.4- Partnership is an association of persons carrying business & in law the firm name is compendious method of describing partners- Deoha F.Guzdar Bombay us C.I.T. Air, 1955 SC 74.

5- Partnership not created by status- The relation of partnership arises from contract and not from status:

and, in particular, the members of a Hindu undivided family carrying on a family business as such, or a Burmese Buddhist husband and wife carrying on business as such, are not partners in such business.

6. Mode of determining extence of partnership - In determining whether a group of persons is or is not a firm, or whether a person is or is not partner in a firm, regard shall be had to the real relation between the parties, as shown by all relevant facts taken together.

Explanation- 1. The sharing of profits or of gross returns arising from property by persons holding a joint or common interest in that property does not of itself make such persons partners.

Explanation- 2 The receipt by a person of a share of the profits of a business, or of a payment contingent upon the earning of profits or varying with the profits earned by a business, does not of itself make him a partner with the persons carrying on the business ;
and i, particular, the receipt of such share or payment -

- a) by a lender of money to persons engaged or about to engage in any business.
 - b) by a servant or agent as remuneration.
 - c) by the widow or child of a deceased partner, as annuity, or
 - d) by a previous owner or part owner of the business , as consideration for the sale of the goodwill or share thereof.
- does not of itself make the receiver a partner with the persons carrying on the business.

7. Partnership at will - Where no provision is made by contract between the partners for the duration of their partnership, or for the determination of their partnership, the partnership is " Partnership at will"

8. Particular partnership - A person may become a partner with another person in particular adventures or undertaking

CHAPTER -III RELATIONS OF PARTNERS TO ONE ANOTHER

9. **General Duties of partners-** Partners are bound to carry on the business of the firm to the greatest common advantage, to be just and faithful to each other, and to render true accounts and full information of all things affecting the firm to any partner or his legal representative.

SHORT NOTE

-sec.9- Sleeping partner can file a suit for rendition of account - Sita Ram vs. Radha Rai, AIR 1968 SC 534.

10. **Duty to indemnify for loss caused by fraud-** Every partner shall indemnify the firm for any loss caused to it by his fraud in the conduct of the business of the firm.

11. **Determination of rights and duties of partners by contract between the partners:** (1) Subject to the provisions of this Act, the mutual rights and duties of the partners of a firm may be determined by contract between the partners, and such contract may be expressed or may be implied by a course of dealing.

Such contract may be varied by consent of all the partners, and such consent may be expressed or may be implied by a course of dealing.

2) **Agreements in restraints of trade-** Notwithstanding anything contained in Sec. 27 of the Indian Contract Act, 1872, such contracts may provide that a partner shall not carry on any business other than that of the firm while he is a partner.

12. **The conduct of the business-** Subject to contract between the partners-

- a) Every partner has a right to take part in the conduct of the business.
- b) Every partner is bound to attend diligently to his duties in the conduct of the business.
- c) any difference arising as to ordinary matters connected with the business may be decided by a majority of the partners, and every partner shall have the right to express his opinion before the matter is decided, but no change may be made in the nature of the business without any consent of all the partners and
- d) every partner has a right to have access to and to inspect and copy any of the books of the firm .

13) **Mutual rights and liabilities** - Subject to contract between the partners -

- a) a partner is not entitled to receive remuneration for taking part in the conduct of the business;
- b) The partners are entitled to share equally in the profits earned, and shall contribute equally to the losses sustained by the firm.
- c) Where a partner is entitled to interest on the capital subscribed by him such interest shall be payable only out of profits.
- d) a partner making, for the purposes of the business, any payment or advance beyond the amount of capital he has agreed to subscribe, is entitled to interest thereon at the rate of six per cent, per annum
- e) The firm shall indemnify a partner in respect of payments made and liabilities incurred by him.
 - i) In the ordinary and proper conduct of the business, and
 - ii) In doing such act, in an emergency, for the purpose of protecting the firm from loss as would be done by a person of ordinary prudence, in his own case, under similar circumstances and
- f) a partner shall indemnify the firm for any loss caused to it by his willful neglect in the conduct of the business of the firm.

Short note

-Sec 13- All the partners are entitled & liable for equal share in loss & profit in absence of any agreement - Mandyala Govindu vs. C.I.T., AIR 1975 SC 2284 : (1976) 1 SCC 248" Asha Ram vs. Ram Chander, 1993 (1) WLN 388.

14. **The property of the firm-** Subject to contract between the partners, the property of the firm includes all property and rights and interests in property originally brought into the stock of the firm, or acquired, by purchase or otherwise, by or for the firm, or for the purposes and in the course of the business of the firm; and includes also the goodwill of the business.

Unless the contrary intention appears, property and rights and interests in property acquired with money belonging to the firm are deemed to have been acquired for the firm

15. **Application of the property of the firm** - Subject to contract between the partners, the property of the firm shall be held and used by the partners exclusively for the purposes of the business.

SHORT - NOTE

-SEC- 15 - Partner can not transfer any part of the property of firm till the continuation of the partnership - Addanki Narayanappa vs. Bhaskara Krishnappa. AIR 1966 SC 1300.

16. **Personal profits named by partners** - Subject to contract between the partners -

- a) If a partner derives any profit for himself from any transaction of the firm or from the use of the property or business connection of the firm or the firm name, he shall account for that profit and pay it to the firm
- b) If a partner carries on any business of the same nature as and competing with that of the firm, he shall account for and pay to the firm all profits made by him in that business.

17. **Right and duties of partners** - Subject to contract (Between the partners -

- a) **after a change in the firm** - Where a change occurs in the constitution of a firm, the mutual rights and duties of the partners in the reconstituted firm remain the same as they were immediately before the change, as far as may be,
- b) **after the expiry of the term of the firm** - Where a firm constituted for a fixed term continues to carry on business after the expiry of that term, the mutual rights and duties of the partners remain the same as they were before the expiry, so far as they may be consistent with the incidents of partnership at will' and
- c) **where additional undertakings are carried out.** - Where a firm constituted to carry out one or more adventures or undertakings carries out other adventures or undertakings, the mutual rights and duties of the partners in respect of the other adventures or undertakings are the same as those in respect of the original adventures or undertaking.

CHAPTER IV - RELATION OF PARTNERS TO THIRD PARTIES

18. Partners to be agent of the firm - Subject to the provisions of this Act, a partner is the agent of the firm for the purposes of the business of the firm.

19. Implied authority of partner as agent of the firm- (1) subject to the provisions of Sec. 22, the act of a partner which is done to carry on, in the usual way, business of the kind carried on by the firm, binds the firm,

The authority of a partner to bind the firm conferred by this section is called his implied authority"

(2) In the absence of any usage or custom of trade to the contract, the implied authority of a partner does not empower him to -

- a) Submit a dispute relating to the business of the firm to arbitration.
- b) open a banking account on behalf of the firm in his own name.
- c) Compromise or relinquish any claim or portion of a claim by the firm,
- d) Withdraw a suit or proceeding filed on behalf of the firm.
- e) admit any liability in a suit or proceeding against the firm
- f) acquire immovable property on behalf of the firm.
- g) transfer immovable property belonging to the firm or
- h) enter into partnership on behalf of the firm.

20) Extension and restriction of partner's implied authority-
The partners in a firm may, by contract between the partners, extend or restrict the implied authority of any partner.

Notwithstanding any such restriction, any act done by a partner on behalf of the firm which falls within his implied authority binds the firm, unless the person with whom he is dealing knows of the restriction or does not know or believe that partner to be a partner.

21., Partner's authority in an emergency - A partner has authority, in an emergency, to do all such acts for the purpose of protecting the firm from loss as would be done by a person of ordinary prudence, in his own case, acting under similar circumstances, and such acts bind the firm.

22. **Mode of doing act to bind firm** : In order to bind a firm, an act or instrument done or executed by a partner or other person on behalf of the firm shall be done or executed in the firm name or in any other manner expressing or implying an intention to bind the firm.
23. **Effect of admissions by a partner** - An admission or representation made by a partner concerning the affairs of the firm is evidence against the firm, if it is made in the ordinary course of business.
24. **Effect of notice to acting partner** - Notice to a partner who habitually acts in the business of the firm of any matter relating to the affairs of the firm operates, as notice to the firm, except in the case of a fraud on the firm committed by or with the consent of that partner.
25. **Liability of a partner for acts of the firm** Every partner is liable, jointly with all the other partners and also severally, for all acts of the firm done while he is a partner.
26. **Liability of the firm for wrongful acts of a partner** - Where by the wrongful act or omission of a partner acting in the ordinary course of the business of a firm, or with the authority of his partners, loss or injury is caused to any third party, or any penalty is incurred, the firm is liable therefor to the same extent as the partner.
27. **Liability of firm for misapplication by partners** - Where -
- a) a partner acting within his apparent authority receives money or property from a third party and misapplies it or,
 - b) a firm in the course of its business receives money or property from a third party, and the money or property is misapplied by any of the partners while it is in the custody of the firm.
- the firm is liable to make good the loss.
28. **Holding out** - (1) Any one who by words spoken or written or by conduct represents himself, or knowingly permits himself to be represented, to be a partner in a firm, is liable as a partner in the firm to any one who has on the faith of any such representation given credit to the firm, whether the person representing himself or represented to be a partner does or does not know that the representation has reached the person so giving credit.
- (2) Where after a partner's death the business continued in the old firm name, the continued use of that name or of the deceased partner's name as a part thereof shall not of

itself make his legal representative or his estate liable for any act of the firm done after his death.

29. Rights of transferee of a partner's interest (1) A transfer by a partner of his interest in the firm, either absolute or by mortgage, or by the creation by him of a charge on such interest, does not entitle the transferee, during the continuance of the firm, to interfere in the conduct of the business or to require accounts, or to inspect the books of the firm, but entitles the transferee only to receive the share of profits of the transferring partner and the transferee shall accept the account of profits agreed to by the partners.

(2) If the firm is dissolved or if the transferring partner ceases to be a partner, the transferee is entitled as against the remaining partners to receive the share of the assets of the firm to which the transferring partner is entitled and for the purpose of ascertaining that share, to an account as from the date of the dissolution.

30. Minors admitted to the benefits of partnership - (1) A person who is a minor according to the law to which he is subject may not be a partner in a firm, but with the consent of all the partners for the time being, he may be admitted to the benefits of partnership.

2) Such minor has a right to such share of the property and of the profits of the firm as may be agreed upon, and he may have access to and inspect and copy any of the accounts of the firm.

3) Such minor's share is liable for the acts of the firm, but the minor is not personally liable for any such act.

4) Such minor may not sue the partners for an account or payment of his share of the property or profits of the firm, save when severing his connection with the firm, and in such case the amount of his share shall be determined by a valuation made as far as possible in accordance with the rules contained in Sec. 48.

Provided that all the partners acting together or any partner entitled to dissolve the firm upon notice to other partners may elect in such suit to dissolve the firm, and thereupon the Court shall proceed with the suit as one for dissolution and for settling accounts between the partners, and the amount of the share of the minor shall be determined along with the shares of the partners.

(5) At any time within six months of his attaining majority, or of his obtaining knowledge that he had been admitted to the benefits of partnership, whichever date is later, such person may give public notice that he has elected to become or that he has elected not to become a partner in the firm, and such notice shall determine his position as regards the firm.

Provided that - if he fails to give such notice, he shall become a partner in the firm on the expiry of the said six month.

(6) Where any person has been admitted as a minor to the benefits of partnership in a firm, the burden of proving the fact that such person had no knowledge of such admission until a particular date after the expiry of six months of his attaining majority shall lie on the persons asserting that fact.

7) Where such person becomes a partner -

- a) his rights and liabilities as a minor continue up to the date on which he becomes a partner, but he also becomes personally, liable to third parties for all acts of the firm done since he was admitted to the benefits of partnership and .
- b) his share in the property and profits of the firm shall be the share to which he was entitled as a minor .

8. Where such person elects not to become a partner.

- a) his rights and liabilities shall continue to be those of a minor under this section upto the date on which he gives public notice.
- b) his share shall not be liable for any acts of the firm done after the date of the notice, and
- c) he shall be entitled to sue the partners for his share of the property and profits in accordance with sub section (4)

9) Nothing in sub sections (7) and (8) shall effect then provisions of Sec. 28.

Short Note

-Sec 30- Suit filed by partnership firm & Partners - Death of one partner does not abate the entire suit - Firm Chunnilal Devkissasn dass vs. Nathu Ram 1990 (2) RLR, 237.

CHAPTER V- INCOMING AND OUTGOING PARTNERS___

31. Introduction of a partner - (1) Subject to contract between the partners and to the provisions of Sec. 30 m no person shall be introduced as a partner into a firm without the consent of all the existing partners.

(2) Subject to the provisions of Sec. 30, a person who is introduced as a partner into a firm does not there by become liable for any act of the firm done before he became a partner.

32. Retirement of a partner -(1) A partner may retire -

- a) With the consent of all the other partners.
- b) in accordance with an express agreement by the partners, or
- c) Where the partnership is at will by giving notice in writing to all the other partners of his intention to retire (23)_ A retiring partner may be discharged from any liability to any third party for acts of the firm done before his retirement by an agreement made by him with such third party and the partners of the reconstituted firm after he had knowledge of the retirement. (3) Notwithstanding the retirement of a partner from a firm, he and the partners continue to be liable as partners to third parties for any act done by any of them which would have been an act of the firm if done before the retirement, until public notice is given of the retirement.

Provided that a retired partner is not liable to any third party who deals with the firm without knowing that he was a partner.

(4) Notices under sub section (3) may be given by the retired partner or by any partner of the reconstituted firm.

33. Expulsion of a partner - (1) A partner may not be expelled from a firm by any majority of the partners, save in the exercise in good faith of powers conferred by contract between the partners.

(2) The provisions of sub section(2), (3) and (4) of Sec. 32 shall apply to an expelled partner as if he were a retired partner.

34. Insolvency a partner - (1) Where a partner in a firm is adjudicated an insolvent he ceases to be a partner on the date on which the order of adjudication is made, whether or not the firm is thereby dissolved.

2) Where under a contract, between the partners the firm is not dissolved by the adjudication of a partner as an insolvent, the estate of a partner so adjudicated is not liable for any act of the firm and the firm is not liable for any act of the insolvent, done after the date on which the order of adjudication is made.

35. Liability of estate of deceased partner - Where under a contract between the partners the firm is not dissolved by the death of a partner, the estate of a deceased partner is not liable for any act of the firm done after his death.

36. **Rights of outgoing partner to carry on competing business -**
(1) an outgoing partner may carry on a business competing with that of the firm and he may advertise such business but, subject to contract to the contrary, he may not -

- a) Use the firm name,
- b) Represent himself as carrying on the business of the firm
- c) Olicit the custom of persons who were dealing with the firms before he ceased to be a partner.

2) **Agreement in restraint of trade -** A partner may make an agreement with his partners that on ceasing to be a partner he will not carry on any business similar to that of the firm within a specified period or within specified local limits; and, notwithstanding anything contained in Sec. 27 of the Indian Contract Act, 1872, such agreement shall be valid if the restrictions imposed are reasonable.

37. **Right of outgoing partner in certain cases to share subsequent profits -**

Where any member of a firm has died or otherwise ceased to be a partner, and the surviving or continuing partners carry on the business of the firm with the property of the firm without any final settlement of a accounts as between them and the outgoing partner or his estate then, in the absence, of a contract to the contrary, the outgoing partner or his estate is entitled at the option of himself or his representatives to such share of the profits made since he ceased to be a partner as may be attributable to the use of his share of the property of the firm or to interest at the rate of six per cent per annum on the amount of his share in the property of the firm.

Provided that: where by contract between the partners an option is given to surviving or continuing partners to purchase the interest of a deceased or outgoing partner, and that option is duly exercised, the estate of the deceased partner or the outgoing partner or his estate, as the case may be, is not entitled to any further or other share of profits, but if any partner assuming to act in exercise of the option does not in all material respects comply with the terms thereof, he is liable to account under the foregoing provisions of this section

38. **Revocation of continuing guarantee by change in firm:**

A continuing guarantee given to a firm or to a third party in respect of the transactions of a firm, is in the absence of agreement to the contrary, revoked as to future transactions from the date of any change in the constitutions of the firm

CHAPTER VI - DISSOLUTION OF A FIRM

39. **Dissolution of firm** - The dissolution of partnership between all the partners of a firm is called "dissolution of the firm"

40. **Dissolution by agreement** : A firm may be dissolved with the consent of all the partners or in accordance with a contract between the partners.

short notes

-Sec 40 - Firm can be dissolved with consent of all the partners or according to contract between the partners - AI 1971 SC 1653 : (1970) 2 SCC 724, AIR 1990 All. 171.

Sec. 40 - Suit filed after 3 years of execution of dissolution deed for rendition of account is barred by limitation - Madan Lal vs. Shiv Narain, 1986 (1) CCC 464.

41. **Compulsory Dissolution** - A firm is dissolved

- a) by the adjudication of all the partners or of all partners but one as insolvent or,
- b) By the happening of any event which makes it unlawful for the business of the firm to be carried on or for the partners to carry it on in partnership.

Provided that : Where more than one separate adventure or undertaking is carried on by the firm, the illegality of one or more shall not of itself cause the dissolution of the firm in respect of its lawful adventures and undertakings.

Short Note

Sec-41 When all the partners or all the partners except one declared insolvent, firm shall be dissolved AIR 1933 Patna 239

42. **Dissolution on the happening of certain contingencies** - Subject to contract between the partners a firm is dissolved -

- a) If constituted for a fixed term, by the expiry of that term
- b) If constituted to carry out one or more adventures or undertakings by the completion thereof.
- c) by the death of a partner.
- d) by the adjudication of a partner as an insolvent.

Short Note

-Sec 42: = On completion of the work, partnership come to an end - Dayalal vs. Harjeevan, AIR 1983 NOC 20(Guj). AIR 1954 Patna 63: Shanta Ram vs. Sripada, AIR 1974 Karanataka 110.

-Sec. 42- Partnership will be deemed to be dissolved after expiry of the fixed period -AIR 1974 SC 1094 AIR 1946 All 489

43. **Dissolution by notice of partnership at will - (1)** Where the partnership is at will the firm may be dissolved by any partner giving notice in writing to all the other partners of his intention to dissolve the firm.

- (2) The firm is dissolved as from the date mentioned in the notice as the date of dissolution or, if no date is so mentioned, as from the date of the communication of the notice.

Short Note

Sec 43. Dissolution of partnership at will Notice in writing to other partners is necessary - Asha Ram vs. Ram chander (1993) (1) WLN 388.

44. **Dissolution by the Court.** At the suit of a partner, the Court may dissolve a firm on any of the following grounds, namely :

- a) That a partner has become of unsound mind, in which case the suit may be brought as well by the next friend of the partner who has become of unsound mind as by any other partner.
- b) That a partner, other than the partner suing, has become in any way permanently incapable of performing his duties as partner.
- c) that a partner, other than the partner suing, is guilty of conduct which is likely to affect prejudicially the carrying on of the business, regard being had to the nature of the business.
- d) that a partner, other than the partner suing, willfully or persistently commits breach of agreement relating to the management of the affairs of the firm or the conduct of its business; or otherwise so conducts himself in matter relating to the business that it is not reasonably practicable for the other partners to carry on the business in partnership with him.

- ~~XXXXXXXXXX~~
- e) That a partner, other than the partner suing has in any way transferred the whole of his interest in the firm to a third party, or has allowed his share to be charged under the provisions of rule 49 of Order XXI of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 or has allowed it to be sold in the recovery of arrears, of land revenue or of any dues recoverable as arrears of land revenue due by the partner.
 - f) That the business of the firm cannot be carried on save at a loss.
 - g) On any other ground which renders it just and equitable that the firm should be dissolved.

45. Liability for acts of partners done after dissolution

- (1) Notwithstanding the dissolution of a firm the partners continue to be liable as such to third parties for any act done by any of them which would have been an act of the firm if done before the dissolution unit public notice is given of the dissolution.

Provided that: The estate of a partner who dies, or who is adjudicated an insolvent or of a partner who not having been known to the person dealing with the firm to be a partner, retires from the firm, is not liable under this section for acts done after the date on which he ceases to be a partner.

- (2) Notices under such- Section 91) may be given by any partner

46. Right of partners to have business wound by after dissolution - On the dissolution of a firm every partner or his representative is entitled, as against all the other partners or their representatives, to have the property of the firm applied in payment of the debts and liabilities of the firm and to have the surplus distributed among the partners or their representatives according to their rights.

47. Continuing authority of partners for purposes of winding up - After the dissolution of a firm the authority of each partner to bind the firm, and the other mutual rights and obligations of the partners, continue notwithstanding the dissolution, so far as may be necessary to wind up the affairs of the firm and to complete transactions begun but unfinished at the time of the dissolution, but not otherwise.

Provided that the firm is no case bound by the acts of a partner who has been adjudicated insolvent, but this proviso does not affect the liability of any person who has after the adjudication represented himself or knowingly permitted himself to be represented as a partner of the insolvent.

Short Note

-Sec 47- Suit on pronote filed by two partners - One partner died
Surviving partner is competent to continue the suit - Abdul
Rehman vs. Rameshwar Dayal, 1004 DNJ (Raj) 59, 1994 (2)
WLC 260, 1994 (1) RLW 40 : 1994 (2) RLR 209

48. **Mode of settlement of accounts between partners** - In setting the accounts of a firm after dissolution, the following rules shall, subject to agreement by the partners, be observed.

- a) Losses, including deficiencies of capital, shall be paid first out of profits, next out of capital and, lastly, if necessary, by the partners individually in the proportion in which they were entitled to share profits.
- b) The assets of the firm, including any sums contributed by the partners to make up deficiencies of capital, shall be applied in the following manner and order:-
 - i) In paying the debts of the firm to third parties.
 - ii) In paying to each partner rateably what is due to him from the firm for advances as distinguished from capital:
 - iii) in paying to each partner rateably what is due to him on account of capital and.
 - iv) The residue, if any shall be divided among the partners in the proportions in which they were entitled to share profits.

49. **Payment of firm debts and of separate debts**- Where there are joint debts due from the firm, and also separate debts due from any partner, the property of the firm shall be applied in the first instance in payment of the debts of the firm, and if there is any surplus, him. The separate property of any partner shall be applied first in the payment of his separate debts and the surplus (if any) in the payment of the debts of the firm.

50 **Personal profits earned after dissolution** - Subject to contract between the partners, the provisions of clause (a) of section 16 shall apply to transactions by any surviving partner or by the representatives of a deceased partner, undertaken after the firm is dissolved on account of the death of a partner and before its affairs have been completely wound up.

Provided that Where any partner or his representative has bought the good will of the firm nothing in this section shall affect his right to use the firm name.

51. **Return of premium on premature dissolution-** Where a partner has paid a premium on entering into partnership for a fixed term, and the firm is dissolved before the expiration of that term otherwise than by the death of a partner, he shall be entitled to repayment of the premium or of such part thereof as may be reasonable, regard being had to the terms upon which he became a partner and to the length of time during which he was a partner unless -

- a)) The dissolution is mainly due to his own misconduct or
- b) The dissolution is in pursuance of an agreement containing no provision for the return of the premium or any part of it.

52. **Rights where partnership contract is rescinded for fraud or misrepresentation -**

Where a contract creating partnership is rescinded on the ground of fraud or misrepresentation of any of the parties thereto, the party entitled rescind is, without prejudice to any other right entitled -

- a) To a lien on or a right of retention of, the surplus of the assets of the firm remaining after the debts of the firm have been paid for any sum paid by him for the purchase of a share in the firm and for any capital contributed by him.
- b) to rank as a creditor of the firm in respect of any payment made by him towards the debts of the firm and
- c) To be indemnified by the partner or partners guilty of the fraud or misrepresentation against all the debts of the firm.

53. **Right to restrain from use of firm name or firm property -**

After a firm is dissolved, every partner or his representative may in the absence of a contract between the partners to the contrary, restrain and other partner or his representative from carrying on a similar business in the firm name or from using any of the property of the firm for his own benefit, until the affairs of the firm have been completely wound up ;

Provided that Where any partner or his representative has bought the goodwill of the firm, nothing in this section shall affect his right to use the firm name.

54. **Agreement in restraint of trade -**

Partners may upon or in anticipation of the dissolution of the firm, make an agreement that some or all of them will not carry on a business similar to that of the firm within a specific period or within specified local limits and notwithstanding anything contained in section 27 of the Indian Contract Act 1872 such agreement shall be valid if the restrictions imposed are reasonable.

Short Note

-Sec-54- Word 'or' used in between' within a specified period or within specified local limits cannot be read as 'and ' - 1969 WLN 570

55. **Sale of good will after dissolution** (1) In settling the accounts of a firm after dissolution the goodwill shall, subject to contract between the partners, be included in the assets, and it may be sold either separately or along with other property of the firm.

2) **Right of buyer and seller of good will** - Where the goodwill of a firm is sold after dissolution, a partner may carry on a business competing with that of the buyer and he may advertise such business, but subject to agreement between him and the buyer, he may not.

- a) use the firm name
- b) Represent himself as carrying on the business of the firm or
- c) Solicit the custom of persons who were dealing with the firm before its dissolution.

3) **Agreement in restraint of trade-** Any partner may, upon the sale of the goodwill of a firm, make an agreement with the buyer that such partner will not carry on any business similar to that of the firm within a specified period or within specified local limits and notwithstanding anything contained in section 27 of the Indian Contract Act, 1872, such agreement shall be valid if the restrictions imposed are reasonable.

Short Note

-Sec 55- Goodwill is a part of assets of the partnership firm - Khusal Khemgal shah vs. Mrs. Khurshed Banu, AIR 1970 SC 1147 : (1970) 1 SCC 415 AIR 1964 SC 11.

CHAPTER VII - REGISTRATION OF FIRMS

56. Power to exempt from application of this chapter -

The State Government of any State may, by notification in the Official Gazette, direct that the provisions of this chapter shall not apply to that state or to any part thereof specified in the notification.

57. Appointment of Registrars (1) The State Government may appoint Registrar of firm for the purposes of this Act, and may define the areas within which they shall exercise their powers and perform their duties (2) Every Registrar shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

58. Application for registration (1) The registration of a firm may be effected at any time by sending by post or delivering to the registrar of the area in which any place of business of the firm is situated or proposed to be situated, a statement in the prescribed form and accompanied by the prescribed fee stating -

- a) The firm name,
- b) The place or principal place of business of the firm.
- c) The names of any other places where the firm carries on business
- d) The date when each partner joined the firm
- e) The names in full and permanent addresses of the partners and
- f) The duration of the firm

The statement shall be signed by all the partners, or by their agents specially authorised in his behalf

- 2) Each person signing the statement shall also verify it in the manner prescribed
- 3) A firm name shall not contain any of the following words - namely -
"Crown", "Emperor", "Empress", "Empire", "Imperial", "King", "Queen", "Royal", or words expressing or implying the sanction, approval or patronage of Government, except when the State Government signifies its consent to the use of such words as part of the firm name by order in writing.

Short Note

Sec 58 - Certificate of registration issued by Registrar of firm show that the firm is registered - 1993 AIHC cases 373 (H.P.)

59. **Registration-** When the Registrar is satisfied that the provision of section 58 have been duly complied with he shall record an entry of the statement in a register called the Register of firms, and shall file the statement.

Short Note

Sec. 59. Registration of firm takes effect from the date of entry in register of firm CIT AP vs. Jaya Laxmi Rice Mills, AIR 1971 SC 1015 : (1971) 1 SCC 280-

60. **Recording of alterations in firm name and principal place of business** - (1) when an alteration is made in the firm name or in the location of the principal place of business of a registered firm, a statement may be sent to the Registrar accompanied by the prescribed fee specifying the alteration, and signed and verified in the manner required under section 58.

2) When the registrar, is satisfied that the provisions of sub - section 91) have been duly complied with he shall amend the entry relating to the firm in the Register in firms accordance with the statement, and shall file it along with the statement relating to the firms filed under section 59.

61. **Noting of closing and opening of branches** -- When a registered firm discontinues business at any place or begins to carry on business at any place, such place not being its principal place of business, any partner or agent of the firm may send intimation thereof to the Registrar, who shall make a note of such intimation in the entry relating to the firm in the Register of firms, and shall file the intimation along with the statement relating to the firm filed under section 59.

62. **Noting of changes in names and addresses of partners** -- When any partners in a registered firms alters his name or permanent address, an intimation of the alteration may be sent by any partner or agent of the firm to the Registrar, who shall deal with it in the manner provided in Section 61.

63. **Recording of changes in and dissolution of a firm** -(1) When a change occurs in the constitution of a registered firm any incoming continuing or outgoing partners and when a registered firm is dissolved any person who was a partner immediately before the dissolution or the agent of any such partner or person specially authorised in this behalf may give notice to the Registrar of such change or dissolution specifying the date thereof and the Registrar shall make a record of the notice in the entry relating to the firms in the Register of Firms, and

shall file the notice in along with the statement relating to the firms files under section 59.

2) **Recording of withdrawal of a minor** - When a minor who has been admitted to the benefits of partnership in a firm attains majority and elects to become or not to become a partner, and the firm is then registered firm; he, or his agent specially authorised in this behalf, may give notice to the Registrar that he has or has not become a partner, and the Registrar shall deal with the notice in the manner provided in sub section (1).

Short Note

Sec 63 - Application for recording change in the register of firm can be sent by post - M/s Harijan Book House vs Registrar of firms, AIR 1988 Guj. 188 1988 Guj L.R. 11: 1988 (1) GLH 1

64. **Rectification of mistakes** -- (1) The Registrar shall have power at all times to rectify any mistake in order to bring the entry in the Register of firms relating to any firm into conformity with the documents relating to that firm filed under this chapter.

2) On application made by all the parties who have signed any document relating to a firm filed under this Chapter, the Registrar may rectify any mistake in such documents or in the records or note thereof made in the Register of firms,

Short Note

Sec 64 - Registration of firm is not affected by omission & error can be rectified - AIR 1954 HP 52.

65. **Amendment of Register by order of Court** -- A court deciding any matter relating to a registered firm may direct that the Registrar shall make any amendment in the entry in the Register of firms relating to such firm which is consequential upon its decision and the Registrar shall amend the entry accordingly.

66. **Inspection of Register and filed documents** (1) The Register of firms shall be open to inspection by any person on payment of such fee as may be prescribed.

2) All statements, notices and intimations filed under this Chapter shall be open to inspection, subject to such conditions and on payment of such fee as may be prescribed.

67. **Grant of copies** -- The Registrar shall on application furnish to any person, on payment of such fee as may be prescribed, a copy, certified under his hand, of and entry of portion thereof in the Register of firms.

68. **Rules of evidence** (1) Any statement, intimation or notice recorded or noted in the Register of firm shall, as against any persons by whom or on whose behalf such statement, intimation or notice was signed, be conclusive proof of any fact there in stated (2) A certified copy of any entry relating to a firm in the Registrar of firms may be produced in proof of the fact of the registration of such firm, and of the contents of any statements intimation or notice recorded or noted therein

Short Note

Sec 68- When necessary entry is made in the register of firm, thereafter registration of firm takes place AIR 1971, SC 1015: 1971 TAx LR 421.

69. **Effect of non-- registration** (1) No suit to enforce a right arising from a contract of or conferred by this Act shall be instituted in any court by or on behalf of any person suing as a partner in a firm against the firm or any person alleged to be or to have been a partner in the firm unless the firm is registered and the person suing is or has been shown in the Register of firms as a partner in the firm.

2) No suit to enforce a right arising from a contract shall be instituted in any court by or on behalf of a firm against any third party unless the firm is registered and the person suing are or have been shown in the Register of firm as partners in the firm

3) The provisions of sub section (1) and (2) shall apply also to a claim of Set - off or other proceeding to enforce a right arising from a contract, but shall not affect -

- a) The enforcement of any right to sue for the dissolution of a firm or for accounts of a dissolved firm, or any right or power to realise the property of a dissolved firm or
 - b) The powers of an official assignee, receiver of Court under the Presidency, towns insolvency Act 1909, or the Provincial insolvency Act, 1920, to realise the property of an insolvent partner.
- 4(This section shall not apply
- a) To firms or to partners in firms which have no place of business in the territories to which this Act extends, or whose places of business in the said territories are situated in areas to which by notification under section 56, this chapter does not apply, or
 - b) to any suit or claim of set off not exceeding one hundred rupees in value which in the presidency towns, is not of a

kind specified in section 19 of the Presidency shall cause Court Act, 1882 or outside the Presidency towns, is not of a kind specified in the Second Schedule to the Provisional small cause Courts Act 1887. or to any proceeding or execution in other proceeding incidental to or arising from any such suit or claim.

Short Note

-Sec 69- In case of unregistered firm, arbitration clause can be invoked for dissolution of firm & rendition of accounts -AIR 1995 SC 715, AIR 1996, SC 2209: 1996 AIRT (SCW) 2696.

70- Penalty for furnishing of false particulars - Any person who signs any statement, amending statement, notice or intimation under this Chapter containing any particulars which he knows to be false or does not believe to be true or containing particulars which he knows to be incomplete or does not believe to be complete, shall be punishable with imprisonment which may extend to three months, or with fine or with both.

71. Power to make rule (1) The State Government may make rules prescribing the fees which shall accompany documents sent to the Registrar, of firms, or which shall be payable for the inspection of documents in the custody of the Registrar of firms or for copies from the Register of firms.

Provided that- Such fees shall not exceed the maximum fees specified in Schedule -I

- 2) The State Government may also make rules-
 - a) Prescribing the form of statement submitted under section 58 and of the verification thereof.
 - b) Requiring statements, intimations and notices under Section 60, 61, 62 and 63 to be in prescribed form and prescribing the form thereof.
 - c) Prescribing the form of the Register of firms, and the mode in which entries relating to firms are to be made therein, and the mode in which such entries are to be amended or notes made therein.
 - d) regulating the procedure of the registrar when disputes arise.
 - e) Regulating the filling of documents received by the Registrar.
 - f) Prescribing conditions for the inspection of original documents.

- g) regulating the grant of copies.
 - h) regulating the elimination of registers and documents.
 - i) Providing for the maintenance and form of an index to the Register of firms, and
 - j) Generally, to carry out the purposes of this chapter.
- 3) All rules made under this section shall be subject to the condition of previous publication.
 - 4) Every rule made by the State Government under this section shall be laid as soon as it is made, before the State Legislature.

CHAPTER VIII SUPPLEMENTAL

- 72. **Mode of giving public notice** -- A public notice under this Act is given.
 - a) Where it relates to the retirement or expulsion of a partner from a registered firm, or to the dissolution of a registered firm, or to the election to become or not to become a partner in a registered firm by a -person attaining majority who was admitted as a minor to the benefits of partnership, by notice to Registrar of firms under section 63, and by publication in the Official Gazette and in at least one vernacular newspaper circulating in the district where the firm to which it relates has its place or principal place of business and.
 - b) In any other case, by publication in the Official Gazette and in at least one vernacular newspaper circulating in the district where the firm to which it relates has its place or principal place of business.
- 73. (Repeals) Rep. by the repealing Act, 1938 (1, of 1938) s. 2 and Sch.
- 74. **Saving:** Nothing in this Act or any repeal effected thereby shall affect or be deemed to affect -
 - a) Any right title interest, obligation or liability already acquired, accrued or incurred before the commencement of this Act, or.
 - b) Any legal proceeding or remedy in respect of any such right, title interest, obligation or liability or any thing done or suffered before the commencement of this Act, or
 - c) Any thing done or suffered before the commencement of this Act or
 - d) any enactment relating to partnership not expressly repealed by this Act, or
 - e) Any rule of insolvency relating to partnership or
 - f) Any rule of law not inconsistent with this Act.

No.F-1(1) 62-2003- XI-- In exercise of the powers conferred under Section 71, sub- section (1) of Indian Partnership (Madhya Pradesh Amendment) Act, 1998 (No.34 of 1998) the State Government hereby enhances the fee prescribed in schedule by 5%

Therefore a new schedule be incorporated as per Section -3 of the said Act as under:-

SCHEDULE - I

Maximum Fees

(See Sub Section (1) of Section 71)

Document or act in respect of which the fee is payable (1)	Maximum fee (2)
Statement under Section 58	Five hundred twenty five Rupees
Statement under Section 60	One hundred Five Rupees.
Intimation under Section 61	One Hundred five Rupees.
Intimation under Section 62	Fifty three Rupees
Notice under Section 63	One hundred five Rupees.
Application under Section 64	Fifty three Rupees
Inspection of the Register of of Section.	Twenty six Rupees
Inspection of documents relating to a firm under sub- Section (2) of Section 66	Twenty - Six Rupees
Copies from the Register of firms under Section 67	Eleven Rupees (For each hundred w words or part thereof)

Provided that the State Government may increase the rate subject to a maximum of five percentage of the above rate in every two years

Note: In case where the applicant requires copies from the Registrar of firms and Societies under Section 67 early i.e. within five working days , he shall file separate application along with double amount of fee and the Competent Authority shall grant copies within five working days "

On behalf of the order of
Governor of Madhya Pradesh

Sd/ A.K.Jain
Under Secretary

THE MADHYA PRADESH
PARTNERSHIP RULES 1951

(Published under Commerce and Industry Departmental Notification No. 4242-896-VII) dated the 2nd June, 1952, in " Madhya Pradesh Gazett", Part IV (C) dated the 6th June, 1952)

1. **Short - Title** - These Rules may be called the Madhya Pradesh Partnership (Registration of Firms) Rules, 1951.
- 2) **Definitions-** In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context :
 - a) "The Act" means the " Indian Partnership Act 1932"
 - b) "Firm" means a firm to which the Act Applies.
 - c) "Registrar" Means the " Registrar of Firms "
- 3) **Form and verification of Statements under Section 58 & 60.**

The statements submitted to the Registrar under Sections 58 and 60 of the Act shall be in Forms I & II respectively, annexed to these rules and shall be verified in the manner set forth in the manner set forth in the note at the bottom of these forms.
- 4) **Form of intimations and notices under Section 61, 62 and 63-**

Intimations and notices under Sections 61,62, 63 (1) and 63(2) of the Act shall be in Forms III , IV, V and VI, respectively, annexed to these rules, with such variations as circumstances may required.
5. **Power of Registrar to make enquiries and investigations -**

The Registrar may, in his discretion, institute such enquiries, or make such investigation, in respect of any matter as may, in his opinion, be necessary for the proper performance of his duties and the administration of the Act or for the settlement of any dispute arising with respect to any firm.

6. **Register of Firms:**

The Register of Firms shall be in English in Form VII annexed to these rules. The name of , and the particulars relating to, each firm shall be entered therein in the order of its registration on a separate page or pages. Each firm shall be assigned a number in a consecutive series commencing with the financial year (1st April). A note of every document filed shall be entered in the register on the page or pages allotted to the firm concerned and shall be signed by the Registrar. The pages after making the entries shall be bound in loose leaf registers in the order of the consecutive number allotted to each firm on registration.

7. **Amendment of entries in Register -**

When an entry made in the Register of firms is to be amended, the amendment shall be shown by drawing a red line, through the entry and making a suitable note in the remark column opposite to the entry concerned and the entry shall be made at the end of the existing entry or entries with suitable cross-reference.

8. **Protest against entries in Register -**

Where any partner or other person interested wishes to dispute, any entry made in Register firms, he shall notify the Registrar of his dispute in writing, and the Registrar shall make any entry at the end of the then existing entries and shall make a red ink reference to the disputed entry in the remarks column against the entry so disputed:

9. **Index to Register of Firms**

A) An index to the Register of firms shall be prepared in English on loose sheets, lettered alphabetically, and shall contain the particulars shown in Form VIII annexed to these rules . A fresh index shall be prepared for each financial year. The name of each firm shall be indexed as soon as the entries relating there to are made in the Register of Firms.

- b) After all the firms registered in a year have been indexed, the index shall be checked by the Registrar who shall attest it in a token of such check and the pages shall then be numbered in ink.
- c) The index for each year shall, after it has been checked, be bound into volumes of convenient size

10. **Translation to be furnished where original not in English:"**

If any document required to be submitted under the Act or any portion of such document is not in the English language, in English translation of such document or portion, certified as correct by at least one partner (or his authorised agent) shall be furnished along with each copy of such document submitted to the Registrar.

11. **Acknowledgement of registration and documents:**

- a) On the Registration of a firm, the Registrar shall grant to the firm an acknowledgement in Form IX annexed to these rules and on the filing of any document required to be filed under the Act, he shall grant to the person at whose instance it is filed an acknowledgement in Form X annexed to these rules.
- b) On every document registered or filed under the Act, the Registrar shall endorse the following particulars:
 - i) The number borne by the firm on the register,
 - ii) The serial number of document and
 - iii) The date of registration or filing.

The Registrar shall also affix his signature and the seal of his office to such document.

12. **Filing of documents**

A separate file shall be maintained in respect of each firm, in which the documents received by the Registrar, relating thereto shall, from time to time, be filed. No document shall be filed by the Registrar unless the fee prescribed therefor has been paid.

13. **Account of and receipt for fees:**

An account of all fees received in the Registrar's office shall be maintained therein in Form XI, A receipt in Form XII shall be granted in respect of every fee received.

14. **Inspection of original documents:**

Subject to the payment of fees prescribed in Rule 19, the Register of Firms and all other documents recorded shall be open to inspection on a written application submitted to the Registrar during business hours. The file of the documents kept in the Registrar's office shall similarly be opened to inspection by any person applying therefor, provided the applicant satisfied the Registrar that he has sufficient interest in the contents of the documents of which he applies for inspection and that a mere inspection of the Register of Firms will not serve his purpose. All inspections of records shall be made in the presence of the Registrar or some person appointed by him in that behalf, The Registrar or the person appointed by him shall not permit the applicant while inspecting any documents to make or cause to be made a copy of any such documents, but he shall permit the applicant to take down in pencil such particulars of the documents as would enable him to apply for a certified copy of any entry or portion thereof in the Register of firms.

15. **Application for copies to be in writing :**

Every application for a copy of any entry in the Register of Firms or portion thereof or a copy of the acknowledgement granted under rule 11 shall be in writing accompanied with the requisite copy fee as prescribed in the Rule 19.

16. **Seal**

The seal used by the Registrar shall bear the words " Registrar of Firms Madhya Pradesh"

17. **Preservation and elimination of registers and records -1.**

The following registers and papers shall be permanently retained.

- a) Register of Firms.
- b) All registered documents of existing firms.
- c) Certificates of registration of dissolved firms
- d) Dissolution orders
- e) References to Legal Remembrancer to Government, Madhya Pradesh.
- f) Legal Remember's opinions.
- g) References to State Government regarding amendments in the Law and replies to the same.
- h) Index Register.
- ii) The following registers and papers shall be destroyed after five years
 - a) Cash Book
 - b) Register of fees
 - c) Papers, other than the above, of firms which have been dissolved
 - d) References to State Government other than above.

- III. The following registers and papers shall be destroyed after two years from the succeeding 1st of April
 - a) Receipt book.
 - b) Despatch Register.
 - c) Other routine correspondence
 - d) Indents for forms etc.
 - e) Treasury Receipts.

- IV The following registers and papers shall be destroyed after one year from the succeeding 1st of April.
 - a) Reminders
 - b) Explanations of delay

18. Cancellation of the registration of defunct firms

- (i) When the Registrar has reason to believe that a registered firm is not carrying on business, or is not in operation, or that it has been finally dissolved, but the

prescribed intimation has not been given, he shall send by post to every partner of the firm at its last known address a letter enquiring whether the firm is carrying on business or is in operation.

- ii) If the Registrar receives an answer from any of the partners to the effect that the firm is not carrying on business or is not in operation or if he does not receive any answer within one month from the date of the posting of the letter, he shall publish in the " Madhya Pradesh Gazette" and send to all the partners by registered post, a notice that at the expiration of three months from the date of that notice the name of the firm mentioned therein shall, unless cause is shown to the contrary, be struck off and the firm shall be dissolved and the registration shall be deemed cancelled.
- iii) At the expiration of the time mentioned in the notice the Registrar shall, unless cause is shown previously by the partners strike the name of the firm off the register, and shall publish notice of the fact in the " Madhya Pradesh Gazette" , and on such publication the firm shall be considered to be dissolved.

19. Fees -

- i) The following fees shall be levied for inspection and grant of copies under the provisions of sections 66 and 67 of the Act.
 - 1) For each inspection under rule 14- fifty paise for inspecting one volume of the register or all documents relating to the firms.
 - 2) For a certified copy of any document or of any extract therefrom under rule 15 - Twenty five paise for each hundred words or part thereof.
 - 3) For certified copy of the acknowledgement of registration granted under rule 11 one rupees.

ii) Fees payable under the Act or these rules by a firm or person shall be credited into the Government treasury and the treasury receipts shall be presented or transmitted to the Registrar's office in token of such payment.

20. **Submission of documents-**

Documents to be lodged with the Registrar shall be printed or type written and may be delivered to him either in person or by post. No fact shall be recorded on a mere oral notice.

21. **Office hours -**

The office of the Registrar shall be open for business (Except on Sundays and holidays) from 11 a.m. to 3 p.m.

FORMS
FORM No.1

(See Rule 3)
Filing Fee ---- Rs. 3)

The Indian Partnership Act 1932.

Application for Registration of firms by the name

Presented or forwarded to the Registrar of Firm for filing.....

We, the undersigned, being the partners of the firm.....
hereby apply for registration of the said firm and for that purpose
supply the following particulars, in plursuance of section 58 of Indian
Partnership Act., 1932.

The Firm's name.....
Place of business.....

- a) Principal place.
b) Other places

Name of partners in full	Date of Joining the firm	Permanent address in full
1	2	3

1.
2.

Duration of the firm.....

Station..... 1)

Dated..... 2)

Signature of the partners or their specially
authorised agents.

I..... son of..... Years of age..... do hereby
declare that the above statement is true and correct to the best of my
knowledge and belief.

Date..
Witness

Signature

I..... Son of..... years of age..... do hereby
declare that the above statement is true and correct to the best of my
knowledge and belief.

Date.....
Witnesses.....

Signature

If any partner is a minor the fact whether he is entitled to the benefits of partnership should be set out herein

NB.= This form must be signed by all partners or their agents specifically authorised in this behalf in the presence of a witness or witnesses who must be either a Gazetted Officer, Advocate, Pleader, or Chartered Accountant.

Here enter name of firm.

FORMS
FORM No.II

(See Rule 3)
Filing Fee ---- Rs. 1)

The Indian Partnership Act 1932.

Statement of Alteration in the name of the Firm
or in the location of the principal place of business.

Presented or forwarded to the Registrar of firms for filing by.....

We the undersigned, being the partners of the firm.*
Registration No.....Date of Registration..... hereby supply
the following particulars in plursuance ofSection 60 (i) of the Indian
Partnershipn Act. 1932

Name of the firm * Regd. No..... Date.....

Previous name	New Name
---------------	----------

Principal place of business	
Previous place (1)	New Place (2)

Station
Date

Signature of the partners or their
Specially authorised agents.

I, Son of..... years of age..... do hereby
declare that the above statement is true and correct to the best of my
knowledge and belief.

Witness.....

Signature

I..... Son of..... years of age..... do hereby
declare that the above statement is true and correct to the best of my
knowledge and belief.

Date.....

Witness

Signature

N.B.- Strike out item not required
* Here enter name of firm.

FORMS
FORM No.III

(See Rule 3)
Filing Fee ---- Rs. 1)

The Indian Partnership Act 1932.

Intimate of change in the place of business.....
(Other than..... Principal place of business)

Presented or forwarded to the Registry of firms for filing by
Under Section 61 of the Indian Partnership Act, 1932, intimation is
hereby given that the changes specified below have occurred in the
place of business of the firm *.....

Registration No..... Date of Registration..... Date of Change.....

- 1) The firm has discontinued business at.....
- 2) The firm has began to carryout business at.....

Station

Date

Signature of any partner
or Agent of the firm.

FORMS
FORM No.iv

(See Rule 4)
Filing Fee ---- Rs. 1)

The Indian Partnership Act 1932.

Intimate of change in the name or permanent address of partner.

Presented or forwarded to the Registry of firms for filing by
Under Section 62 of the Indian Partnership Act, 1932, intimation is hereby given that the changes specified below have occurred in the name or/and permanent address of partners in the firm*.....

Name of partner -

Previous name in full (1)	/	New Name in full (2)
------------------------------	---	-------------------------

Permanent address of partner -

Previous permanent address in full (1)	Present permanent address in full (2)
--	---

Station.....

Date.

Signature of any partner or agent
of the firm.

N.B.- Strike out item not required.

* Here enter name of firm.

FORMS
FORM No. V

(See Rule 4)
Filing Fee ---- Rs. 1)

The Indian Partnership Act 1932.

**Notice of change in the constitution of the firm
or of the dissolution of the firm ***

Presented or forwarded to the Registry of firms for filing -----by
Under Section 63(1) of the Indian Partnership Act, 1932, intimation is
hereby given that the -

(i) The constitution of the firms.....
Registration No..... date of Registration..... has been
altered as follows :

Name and full address of the incoming partner and date of his joining the firm (1)	Name and full address of the outgoing partner and date of his ceasing to be partner. (2)
---	---

Station.....
Date.....

Signature of the incoming conti-
nuing or outgoing partner or of
his specially authorised agent.

(2) The firm *Registration No..... Date of
registration..... has been dissolved with effect from the.....

Station
Date

Signature of the person who was a
partner immediately before the
dissolution or of his specially
authorised agent.

NB- Strike off item not required.
* Here enter the name of the firm

FORMS
FORM No.VI

(See Rule 4)
Filing Fee ---- Rs. 1)

The Indian Partnership Act 1932.

**Notice of Election by person admitted to the benefit of
partnership on attaining majority**

Presented or forwarded to the Registry of firms for filing by
Under Section 63(2) of the Indian Partnership Act, 1932, intimation is
hereby given that admitted to the benefit of partner
ship in the firm*Registration No.....Date of
Registration..... having now attained majority elects to become/
elects not to become a partner of the said firm.

Station
Date.....

Signature of the person
Electing or of his specially
authorised agent.

* Here enter name of firm

F O R M S
FORM No.VII

Register of firms

Maintained under section 59 of the Indian Partnership Act 1932.

1. Serial Number of firm
2. Name of firm -
3. Date of registration -
4. Duration of the firm-

5.	Address	Date of Change	Remarks
	1	2	3

6. Partners

Name of Partners	Address	Date of		Remarks
		Joining	Ceasing	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

7. Principal place of business and changes therein -

Particulars regarding the place	Date of change	Remarks
(1))2	(3)

8) Other places of business

Name of place	Date of		Remarks
	Opening	Ceasing	
1	2	3	4

9. Name of firm

Serial No. of the document	Description of document	Date of filing	Signature of Registrar
1	2	3	4

FORM No. VIII
(See Rule 9)
Index to the Register of firm

Name of of firm	Names of partners	Principal Place of business	Trade	Volume No.	First page of entry on the register	No. borne on the register
1	2	3	4	5	6	7

FORM No. IX
(See Rule 11)a_
Acknowledgement of Registrar of firms

The Registrar of firms Madhya pradesh, hereby acknowledges the receipt of the statement prescribed by Section 58 (i) of the Indian Partnership Act. 1932, The Statement has been filed and the name of the firm..... has been entered in the Register of firm as..... No..... of 19.

Seal Registrar of firm

Bhopal
The Day of, ...19

* Here enter name of firms

FORM No. X
(See Rule 11 (a)

The Registrar of firms Madhya pradesh, hereby acknowledges the receipt of the under mentioned document and of the fee noted against..... for the same and intimates that..... been..... pursuant to section of the Indian Partnership Act. 1932.

Seal Registrar of firm

Bhopal
The Day of, ...19
Forwarded to the Managing Agent/ Partner of the..... with reference to their/his letter No..... dated the.....

Registrar of firms.

FORM No. XI
(See Rule 13)
Office of the Registrar of firms

Register of fee

Date of receipt	Amount received	From whom received	on what account	Date of remittance to Govt. treasury
1	2	3	4	5

FORM No. XII
(See Rule 13)
Receipt for fee

Received from.....

The sum of rupees (In words)
being the fee for --

Rs. P.

Filing Statement
Filing notice
Inspection of
Copy of (Number of words)

Total

Station
Dated